শৰ্মা হাৰ্ডৱেৰ
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 239 | गुवाहाटी | शनिवार, 4 अप्रैल, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

ट्रंप ने विदेशी ब्रांडेड दवाओं पर ठोका सौ प्रतिशत टैरिफ, मचा कोहराम — पेज 2

कांग्रेस घुसपैठ एवं दंगा कराती थी, भाजपा उन्हें निकाल बाहर करती... — पेज 3

मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब... — पेज 5

जेम्स रोड्रिगेज अस्पताल में भर्ती, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले कोलंबिया को... — पेज 7

door graphy Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

मनुष्य कितना भी बड़ा क्यो न बन जाए उसे हमेशा अपना अतीत याद करते रहना चाहिए।

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर

असम को नहीं बनने देंगे लव जेहाद एवं लैंड जेहाद की धरती : योगी

बरपेटा (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार दीपक कुमार दास के पक्ष में बरपेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस एवं एआईयूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई, जबकि एआईयूडीएफ को भी बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने असमवासियों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है और असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है। राजग का संकल्प है कि असम को लव जेहाद-लैंड जेहाद की धरती नहीं बनने देंगे। यहां घुसपैठ नहीं होने देंगे। कांग्रेस व यूडीएफ की घुसपैठियों के जरिये डेमोग्राफी बदलने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। एक-एक घुसपैठी को चिह्नित कर यहां से बाहर करने की भी व्यवस्था हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने तय किया है कि असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनने देंगे और दंगाइयों को निकाल बाहर करेंगे। कांग्रेस एवं एआईयूडीएफ को जब भी अवसर मिला, इन्होंने भारत व भारतीयता को अपमानित किया। एआईयूडीएफ असम में घुसपैठ की जननी है। घुसपैठियों के बल पर असम की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस उनकी सहयोगी बनकर असम की संस्कृति से खिलवाड़ कर रही है। वहीं राजग सरकार असम की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करते हुए हर घुसपैठिए को बाहर कर डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश को विफल कर रही है। उन्होंने असमवासियों को रंगाली बिहू उत्सव की शुभकामना देते हुए असम को भारत के गौरव की धरा बताया और कहा कि हर भारतवासी यहां मां कामाख्या के दर्शन करने आता है। यहां की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व समृद्ध परंपरा ने *एक भारत-श्रेष्ठ भारत* के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया है। वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव व माधव देव की पावन धरा ने नई ऊंचाई के साथ इसे एकता, भक्ति व मानवता के संदेश की भूमि के रूप में परिवर्तित किया है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के साथ जैव विविधता के लिए जग विख्यात है। अहोम राजवंश ने इसी पावन धरा में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाकर अहोम की समृद्ध संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाकर भारत की रक्षा में योगदान दिया था। अहोम राजवंश के महान नायक लचित बरफुकन का अदम्य साहस, शौर्य व पराक्रम भारतीय युवाओं के -शेष पृष्ठ दो पर

आदिवासियों के लिए पीएम मोदी हिमंत का रोडमैप तैयार : अमित शाह

पलाशबारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसकी सरकार ने असम को घुसपैठियों के हाथों में सौंप दिया है। कामपुर और पलाशबाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि घुसपैठिए गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले दस वर्षों में भाजपा सरकार ने असम भर में कथित अतिक्रमण से लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन मुक्त कराई है। शाह ने मतदाताओं से भाजपा को फिर से चुनने का आग्रह करते हुए कहा कि नया जनादेश सरकार को पूरे असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने में सक्षम बनाएगा। हिमंत विश्व शर्मा का समर्थन करते हुए शाह ने मतदाताओं से उन्हें फिर से सत्ता में लाने की अपील -शेष पृष्ठ दो पर

देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध : केंद्रीय गृहमंत्री

ग्वालपाड़ा (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दुधनै के कॉलेज ग्राउंड मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवार टंकेश्वर राभा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वह असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार देश से अवैध विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्वालपाड़ा जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम को अशांत बनाए रखा और राज्य की संस्कृति के संरक्षण के -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण गोलकगंज में शाह की सभा रद्द

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण असम के धुबड़ी जिले के गोलकगंज में शुक्रवार को होने वाली पहली चुनावी रैली रद्द कर दी गई। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, शाह गुवाहाटी से गोलकगंज के लिए रवाना हुए थे लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका, जिसके -शेष पृष्ठ दो पर

यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से संचालित गिरोह का किया भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने शुक्रवार को पाकिस्तान से संचालित एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल्स के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहकर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे संपत्तियों और राजनीतिक व्यक्तियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। एटीएस ने समय रहते कार्रवाई कर चार -शेष पृष्ठ दो पर

असम में चुनावों के लिए 48 घंटे का मौन अवधि 7 से : चुनाव आयोग

नई दिल्ली। असम चुनाव के लिए मौन अवधि 7 अप्रैल को शाम 5:00 बजे से शुरू होगी और 9 अप्रैल को शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगी। इस बात की जानकारी चुनाव आयोग ने दी। आयोग ने आगे कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में चुनाव के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के अड़तालीस घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण सहित किसी भी माध्यम से चुनाव संबंधी कोई भी सामग्री प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। तदनुसार, आयोग दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनल और केबल -शेष पृष्ठ दो पर

बराक घाटी की 9-11 सीटों पर होगी भाजपा की जीत : सीएम

सिलचर (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि बराक घाटी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 9 से 11 सीटें हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बराक घाटी को एक प्रमुख चुनावी रणक्षेत्र के रूप में रेखांकित किया, जहां पार्टी को महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी की संगठनात्मक ताकत और जमीनी स्तर पर लगातार पहुंच ने मतदाताओं के बीच अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने विशेष रूप से हैलाकांदी को लेकर विश्वस जताया और कहा कि भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र को जीतने के प्रति सौ प्रतिशत आश्वस्त है। अल्गापुर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच काफी चर्चा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी नतीजे अंततः पार्टी के जमीनी प्रदर्शन को ही दर्शाएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष के चुनाव प्रचार की सवाल उठाया। उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए पूछा कि उन्होंने कितनी जनसभाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने से बचती है, इसके बजाए अधिक से अधिक सभाएं करने तथा मतदाताओं से सीधे जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करती है। पार्टी की व्यापक संभावनाओं पर अपना विश्वस दोहराते हुए, डॉ. शर्मा ने पूरे असम में 90 से 100 सीटों के जीत का अनुमान जताया और साथ ही भाजपा की समग्र चुनावी रणनीति में बराक घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। ज्ञात हो, असम विधानसभा चुनाव में आगामी 9 अप्रैल को मतदान तथा मतों की गिनती आगामी 4 मई को होगी।

राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने पर आप में बढ़ी तकरार, बयानबाजी तेज

नई दिल्ली (हि.स.)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाने के बाद पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गयी है। राघव चड्ढा ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश बताया है, जबकि पार्टी के अन्य नेताओं ने उन पर गंभीर मुद्दों पर सदन में चुप रहने का आरोप लगाया है। राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें खामोश करवाया गया है, लेकिन वे हारे नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनकी आवाज पर रोक क्यों लगाई जा रही है। चड्ढा ने कहा कि वह संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई, एयरपोर्ट पर महंगा खाना, डिलीवरी कर्मियों की समस्याएं, मिलावटी भोजन, टोल और बैंक से जुड़ी परेशानियां उठाते रहे हैं। उन्होंने इसे जनता के हित -शेष पृष्ठ दो पर

चुनाव 26 : दिसपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार से लड़ाई हुई दिलचस्प

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री की बैठक, दिसपुर सीट पर फोकस

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में अब विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सत्ताधारी एवं विपक्ष की पूरे राज्य में लगातार चुनावी सभाएं आयोजित हो रही हैं। वहीं, दूसरी ओर राजधानी की दिसपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी जयंत कुमार दास के प्रचार अभियान ने भी जोर पकड़ लिया है। ज्ञात हो कि, जयंत कुमार दास लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सक्रिय कार्यकर्ता थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर निर्दल चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। जयंत कुमार दास के समर्थन में विभिन्न दल और संगठन एकत्र होते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार -शेष पृष्ठ दो पर

मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश : आयोग

नई दिल्ली (हि.स.)। चुनाव आयोग ने 2026 के राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों पर भी लागू होगी और इस दिन के लिए किसी भी प्रकार की वेतन कटौती नहीं की जाएगी। आयोग ने शुक्रवार को कहा कि असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, -शेष पृष्ठ दो पर

घुसपैठ पर सख्त त्रिपुरा हाई कोर्ट, सरकार से तीन महीने में मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नई दिल्ली। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भाजपा शासित राज्य सरकार से कहा है कि वह सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट अगले तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करे। एक वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता में एक डिवीजन बेंच ने यह निर्देश गुरुवार को तीन व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देबबर्मा भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद त्रिपुरा सरकार इस समस्या को हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एंथनी देबबर्मा ने कहा कि डिवीजन बेंच ने राज्य -शेष पृष्ठ दो पर

पीओके पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख का बड़ा बयान

जल्द होगी घर वापसी

नई दिल्ली। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) बहुत जल्द भारत में शामिल हो सकता है। साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए बदलावों की भी सराहना की। उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां के लोग खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वहां के लोग जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं और भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके के लोग जम्मू-कश्मीर में हो रहे विकास को देख रहे हैं और उससे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि -शेष पृष्ठ दो पर

अमेरिका ने माना- ईरान ने मार गिराया एफ-35 जेट, रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी फाइटर जेट गिराया गया है, जिसके बाद पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। वहीं ईरानी मीडिया ने पायलट के पकड़े जाने तक की बात कही है, लेकिन इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया है। इसके बाद किसी भी जीवित व्यक्ति को खोजने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि, इस पर अभी तक पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि गिराए गए जेट का पायलट देश के अंदर गिरा और संभव है कि उसे पकड़ लिया गया हो। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पायलट ने इजेक्ट किया था, जबकि अन्य में बताया गया कि धमाका इतना बड़ा था कि उसके बचने की संभावना -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान में परिवहन मालिकों की चेतावनी-

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से बंद हो जाएंगे कारोबार

इस्लामाबाद (हि.स.)। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने आर्थिक और सामाजिक चिंता को गहरा कर दिया है। घोषित नई दरों के बाद पेट्रोल 458 रुपए और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इस फैसले के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी समेत कई राजनीतिक और व्यावसायिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रमुख हाफिज नईम-उर-रहमान ने इसे अस्वीकार्य और घोर अन्याय बताया है। वहीं, परिवहन मालिकों ने चेतावनी दी है कि -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

ट्रंप ने विदेशी ब्रांडेड दवाओं पर ठोका सौ प्रतिशत टैरिफ, मचा कोहराम

वाशिंगटन। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर घूम फिर कर टेरिफ पर आ गए हैं। इस बार ट्रंप ने 100 प्रतिशत तक भारी भरकम टेरिफ लगाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में बड़ा फेरबदल करते हुए विदेशी ब्रांडेड दवाओं पर 100 प्रतिशत तक टेरिफ ठोकने की बात कही है। ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर उन फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा जो कंपनी दवाइयां अमेरिका के बाहर बनाती हैं। इस आदेश के साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इन दवा कंपनियों को ना सिर्फ अपनी कीमतें कम करनी होंगी बल्कि उनका उत्पादन भी अमेरिका के अंदर ही करना होगा। नए नियमों के मुताबिक जो कंपनियां आंशिक रूप से अपना उत्पादन अमेरिका शिफ्ट कर देंगी उन्हें 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं आदेश का पालन ना करने वाली कंपनियों से 100 प्रतिशत टेरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप का दावा है कि इस फैसले से ना सिर्फ दवाइयां सस्ती होंगी बल्कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं ट्रंप ने स्टील, एलुमिनियम और तांबे जैसे मेटल उत्पादन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। जिसमें कई सामानों पर टेरिफ घटा दिया गया और टैक्स वसूलने के नियमों में भी बदलाव किया गया। ट्रंप प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 232 के तहत स्टील, एलुमिनियम और तांबे के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क बरकरार रखा है। वहीं कुछ मेटल्स पर टेरिफ 25 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा जिन उत्पादों में मेटल की मात्रा 15 प्रतिशत से कम है, उन्हें टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है। हालांकि इसके टैक्स वसूलने के तरीके में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। अब यह शुल्क आयातित वस्तु के उस मूल्य पर लगेगा जो अमेरिकी ग्राहक भुगतान करते हैं। ना कि केवल धातु की मात्रा पर। अब यह समझिए कि ट्रंप के 100 प्रतिशत टेरिफ के पीछे की वजह क्या है? दरअसल एक साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुक्ति दिवस के नाम पर एक खास कानून आईईपीए यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत पूरी दुनिया पर भारीभरकम टैक्स लगा चुके थे। जिससे दुनिया के कई देश भड़क गए और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जिसके बाद इस साल फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन पुराने टैक्सों को अवैध और गैरकानूनी करार दिया। जिसका असर यह हुआ कि ट्रंप सरकार को 166 अरब डॉलर उन लोगों को वापस करने पड़ रहे हैं जिनसे यह टैक्स वसूला गया था। अब ट्रंप इसी भारीभरकम नुकसान की भरपाई करने और अपनी बात ऊपर रखने के लिए यह नियम लेकर आए हैं। घोषणा में स्पष्ट किए गए अनुसार, जेनेरिक दवाओं को छूट मिलने से भारत को काफी फायदा होगा। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों का दबदबा है। इसलिए, अल्पावधि में जेनेरिक दवाओं को छूट मिलने से एक सुरक्षा कवच मिलेगा और कम लागत वाली दवाओं के निर्यात में आसानी होगी, जो अमेरिका के साथ भारत के दवा व्यापार की रीढ़ हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया,जेनेरिक दवाएं, जो भारतीय फार्मा निर्यात का अधिकांश हिस्सा हैं, टैरिफ से मुक्त हैं, लेकिन वाणिज्य विभाग जेनेरिक दवाओं की रीशॉर्डिंग की स्थिति का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार टैरिफ का पुनर्मूल्यांकन करेगा।

केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश, ईमानदारी से काम करने वाले व्यवसायियों को डरने की जरूरत नहीं : सरावगी

पटना (हिंस)। जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह व्यापार और जीवन को सुगमता की ओर बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार सुगम, सरल और पारदर्शी बनेगा। इससे छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और युवाओं को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। उन्होंने इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में *ईज ऑफ डूइंग बिजनेस* और विश्वास आधारित शासन को नई मजबूती मिल रही है, जो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जन विश्वास विधेयक रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित है जहां शासन का आधार दंड नहीं, न्याय और विश्वास था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कल्पना है कि यह देश विश्वास के आधार पर आगे बढ़े और उसी विश्वास से विकसित भारत 2047 का रास्ता तैयार हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राम राज्य की चर्चा करते हुए कहा कि उस दौर में हर व्यक्ति को सुना जाता था, हर नागरिक को सम्मान मिलता था, और लोग बिना भय के जीवन जीते थे। जन विश्वास विधेयक उसी दिशा में एक और कदम है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार जनता पर भरोसा कर रही है, उन्हें परेशान करने के बजाय सुविधा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक नए भारत को एक नए प्रकार के *रामराज्य* की ओर ले जाने का प्रयास है जहां शासन सेवा करे, भरोसा करे और जनता के जीवन को आसान बनाया जाए, जहां विश्वास और भरोसा हो। उन्होंने बताया कि इस संशोधन विधेयक के जरिए सैकड़ों पुराने कानूनों में सुधार किया गया है। इनमें से कई कानून तो ऐसे हैं जो ब्रिटिश राज के समय से चले आ रहे थे। ये कानून आज के समय में अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जन विश्वास विधेयक 2026 देश के व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब छोटी-छोटी कागजी या प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए जेल नहीं होगी। पहली बार गलती होने पर सिर्फ चेतावनी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर मामूली जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ईमानदारी से काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सराकर का लक्ष्य है कि लोग बिना डर के व्यापार करें, आगे बढ़ें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। यही *ईज ऑफ डूइंग बिजनेस* की असली भावना है।

राहुल ने ओछी टिप्पणी कर पूर्वोत्तर का किया अपमान : मौर्य

लखनऊ (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा पर ओछी टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लखनऊ में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पर ओछी टिप्पणी कर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि उनका पांच दफा का सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता का अनुभव कुंठा से लबालब है। आम आदमी की तो छोड़िए, राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भी किसी क्षण अपमानित कर सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हिमंता विश्व शर्मा पर उनकी ओछी टिप्पणी समूचे उत्तर-पूर्वी राज्यों का अपमान है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी हार का शतक लगाने की जल्दबाजी है, असम में भाजपा की जीत उनकी ख्वाहिश जरूर पूरा करेगी। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही सरकार : यादव

जौनपुर (हिंस)। यूपी के जौनपुर स्थित सरायख्वाजा क्षेत्र के जंगीपुर कला स्थित रघुवर गंगा स्मारक बालिका विद्यालय परिसर में शुक्रवार को आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक एमएलसी और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लालबिहारी यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है और शिक्षकों व युवाओं की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। लालबिहारी यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है।

देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, घबराहट में बुकिंग न करें : इंडियन ऑयल

नई दिल्ली (हि.स)। देश की सबसे बड़ी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शुक्रवार को कहा कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन करीब 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। इसलिए घबराहट में बुकिंग न करें। आईओसी ने एक बयान में कहा कि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति स्थिर एवं पर्याप्त है और घरेलू उपलब्धता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। कंपनी ने कहा कि देश में रोजाना लगभग 28 लाख सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, जो सामान्य स्तर के बराबर है। घबराहट से प्रेरित मांग को रोकने के लिए उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे समय से पहले बुकिंग न करें। कंपनी के अनुसार वह प्रतिदिन करीब 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति कर रही है, जो मौजूदा तनाव से पहले के सामान्य स्तर के अनुरूप है। आईओसी ने बताया कि करीब 87 फीसदी *रीफिल बुकिंग* डिजिटल माध्यमों से की जा रही हैं, जबकि सही उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड (ओटीपी) आधारित प्रणाली से वितरण की पुष्टि की जा रही है। उपभोक्ताओं को एसएमएस (संदेश) और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) जैसे डिजिटल माध्यमों से एलपीजी *रीफिल बुक* (सिलेंडर फिर भरवाने) करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सोशल मीडिया और उपभोक्ता शिकायतों के जरिए कुछ एलपीजी वितरकों को अनियमितताओं की जानकारी मिली है। काला बाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए विभिन्न विभागों के कई दल एलपीजी वितरक केंद्रों पर अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 7,500 से अधिक निरीक्षण किए गए और 141 वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 5 को निलंबित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों और अन्य तेल एवं गैस विपणन कंपनियों के साथ मिलकर करीब 68 हजार छापे भी डाले गए हैं।

पृष्ठ एक का शेष

असम को नहीं बनने ...

लिए प्रेरणा रहा है। असम ने मेहनत, परिश्रम व पुरुषार्थ से चाय की चुस्की को दुनिया तक पहुंचाया। असम अब चाय के साथ चिप के उत्पादन की केंद्रभूमि भी बन रही है। मुख्यमंत्री योगी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भारत रत्न केवल एक खानदान के लोगों को प्राप्त होता था। असम के संगीत एवं संस्कृति की पहचान भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मोदी सरकार ने और गोपीनाथ बरदलै को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिया। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्षों तक असम में अराजकता, दंगा, कर्फ्यू, घुसपैठ को बढ़ावा देकर सुरक्षा में सेंध लगाई और विरासत को अपमानित किया। कांग्रेस को मां कामाख्या कॉरिडोर, काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडा संरक्षण, असम एवं पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी याद नहीं आई। आज पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, रेल, एयरपोर्ट व इनलैंड वाटरवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है और यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से संवाद करते हुए कहा कि देश में जहां-जहां राजग सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहां-वहां विकास और विरासत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामजन्मभूमि के लिए आंदोलन चला। असम से भी रामभक्त जाते थे, नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन, कांग्रेस ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं। उसके सहयोगी दलों ने भी राम के अस्तित्व को नकारा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो 500 वर्ष की तमन्ना पूरी हुई और अयोध्या में भव्य राममंदिर बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज दंगा, कर्फ्यू और माफिया मुक्त है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, वहां सब है चंगा। यूपी की सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां धर्मस्थलों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। यदि किसी ने दंगा करने का दु:स्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दलितों, गरीबों, जनजाति समुदाय में बांट दी जाती है। घुसपैठियों या दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता। कांग्रेस व एआईयूडीएफ ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को बसाकर डेमोग्राफी बदलने और असमवासियों के हक, राशन, मकान व जमीन पर जबरन कब्जे का काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष से एक भी दंगा नहीं हुआ। सरकार विकास और गरीब कल्याण के कार्यों को बढ़ा रही है। उज्ज्वला योजना कनेक्शन, भरपूर बिजली, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपए तक का लाभ, युवाओं को नौकरी व रोजगार, गरीबों के लिए फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। असम के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को स्पेशल पैकेज देकर सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य केवल भाजपा व राजग सरकार ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस व एआईयूडीएफ के पास विजन और कार्य करने की क्षमता नहीं है। ये केवल भारत की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। योगी ने असमवासियों से अपील की कि इन्हें सेंध लगाने की छूट नहीं देनी है।

आदिवासियों के लिए पीएम...

की और वादा किया कि सरकार हर एक घुसपैठिए को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। अपने रुख को दोहराते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठ गरीबों के अधिकारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है और राज्य के युवाओं के लिए अवसरों को सीमित कर रही है। लपाड़ा जिले के दुधनै में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने इसे बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनीं। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और यहां असम में मुख्यमंत्री हैं-दोनों के पास राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप है। अगर लोग भाजपा को लगातार तीसरी बार जनादेश देते हैं, तो इसे (रोडमैप) आगे बढ़ाया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी कल्याण की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासियों के विकास पर केवल 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में उनके लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए दिए। गृह मंत्री ने ग्वालपाड़ा को *मिनी असम* करार दिया, क्योंकि वहां राभा, बोड़ो, हाजोंग और कोच सहित कई जनजातियों के लोगों के अलावा आदिवासी चाय बागान श्रमिक रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा ही इन लोगों का विकास सुनिश्चित कर सकती है। शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को डराने के लिए अफवाहें फैला रही है कि वे यूसीसी से प्रभावित होंगे, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है और कोई भी आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने आदिवासियों की कला, संस्कृति, भोजन, वस्त्र, संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। मैं सहकारिता मंत्री के रूप में इसे सुनिश्चित करूंगा।

देश से घुसपैठियों को बाहर ...

लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि भाजपा असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास कर रही है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा शासन में लगभग 10 हजार लोगों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापस लाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी पांच वर्षों में यदि भाजपा सत्ता में लौटती है तो राज्य में कोई हिंसात्मक घटना नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु नए उद्योग स्थापित करने का वादा भी किया। अपने संबोधन के अंत में शाह ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में एक भी वोट न देने की अपील करते हुए असम में विकास और स्थिरता के लिए भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया।

असम में चुनावों के ...

नेटवर्क यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रसारित/दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की सामग्री में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री न हो। इसमें जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी शामिल है। आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126ए के तहत आयोग ने अधिसूचित किया है कि 9 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे के बीच एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों का प्रसार निषिद्ध है। आयोग ने कहा कि आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन दो साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय है। आयोग सभी मीडिया संस्थानों को सलाह देता है कि वे इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन आयोग की भावना के अनुरूप करें। बुधवार को आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से असम, केरल और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ 282 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित की। असम के लिए कुल 136 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 51 सामान्य पर्यवेक्षक, 35 पुलिस पर्यवेक्षक और 50 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं।

चुनाव 26 : दिसपुर सीट...

को असम पब्लिक वर्कस (एपीडब्ल्यू) के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा पूरी तरह से जयंत दास का समर्थन करने का एलान किया। अभिजीत शर्मा और जयंत दास ने गुरुवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अपनी चुनावी रणनीतियों का खुलासा किया। संवाददाता सम्मेलन से पहले जयंत दास के प्रतीक चिह्न ईंट अभिजीत शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। प्रत्याशी के बेलतला स्थित घर में क्षेत्र के कई संगठनों का नेतृत्व एकत्र हुआ। संगठनों के नेताओं ने कहा कि दिसपुर के निवासियों को ध्यान रखना होगा कि हमें ईंट के चुनाव चिह्न पर मतदान करना होगा। मीडिया को संबोधित करते हुए जयंत दास ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रद्युत बरदलै एक व्यक्ति के एजेंट थे, ऐसे में उस व्यक्ति का विश्वस नहीं किया जा सकता यह बात आज प्रमाणित हो गयी है। ज्ञात हो कि बोरदलोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उन्हें टिकट भी मिल गया। इसी बात को लेकर अभितजीत शर्मा ने कहा कि पैराशूट लैंडिंग करने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि लोगों के बीच मौजूद व्यक्ति को वोट दें। आज समस्या राज्य में बड़ी है इसलिए जयंत दास का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि दिसपुर के लोगों ने सब कुछ समझ लिया है। जयंत दास ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ दिल्ली को खुश करने के लिए है। उन्होंने कहा कि भाजपा 125 सीटों पर मुकाबला करें लेकिन दिसपुर छोड़ दें। मैं (जयंत दास) एक छोटा कण हूं। छोटे-छोटे कण मिलकर ही पार्टी बनी थी। आज पार्टी से ऐसे लोगों बाहर आना पड़ रहा है। मैं अर्जुन की आंख की तरह अब केवल दिसपुर को देख रहा हूं। उन्होंने दिसपुर की जनता से उन्हें जिताने का आह्वान किया। उधर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बीती रात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में दिसपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक आगामी चुनावों के मद्देनजर रणनीति तय करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। बैठक में दिसपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युत बरदलै सहित समस्त जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान क्षेत्र में चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गुवाहाटी की सांसद बिजुली कलिता मेधी और पूर्व राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी विचार-विमर्श में भाग लेते हुए दिसपुर सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर जोर दिया।

मतदान के दिन सभी ...

नगालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा—पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत प्रत्येक मतदाता, जो किसी भी संस्थान, उद्योग या व्यवसाय में कार्यरत है, मतदान के दिन सवेतन अवकाश का हकदार होगा। यदि कोई नियोक्ता इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, जिससे सभी मतदाता बिना किसी बाधा के अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें।

घुसपैठ पर सख्त त्रिपुरा ...

सरकार से कहा है कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए उठाए गए कदमों पर अगले तीन महीनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पूर्वोत्तर राज्य की बांग्लादेश के साथ 856 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से लगभग 85 प्रतिशत सीमा बाड़बंदी की गई है। न्यायालय के निर्देश का जवाब देते हुए रंजीत देबबर्मा ने कहा कि घुसपैठ को तुरंत रोकना चाहिए ताकि राज्य की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विधायक ने कहा कि जबकि अन्य राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए घुसपैठ विरोधी अभियान चला रहे हैं। त्रिपुरा सरकार इस मामले में सही तरीके से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने कई मंचों पर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मुझे उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे मुझे न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब, न्यायालय इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगा।

राघव चड्ढा को उपनेता पद ...

में किया गया काम बताया और कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर चड्ढा पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चड्ढा बड़े और गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से बचते रहे हैं। संसद में गंभीर मुद्दे उठाने जरूरी हैं, सिर्फ हल्के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने गुजरात में कार्यकर्ताओं पर केस और गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप रहने पर सवाल उठाया। भारद्वाज ने कहा कि जब पार्टी और उसके नेताओं पर कार्रवाई हो रही थी, तब चड्ढा ने खुलकर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को निडर होकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। विपक्ष को डटकर लड़ना होगा। निडर होकर सरकार से सवाल पूछने होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भी चड्ढा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से चड्ढा *डर गए हैं* और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। ढांडा ने आरोप लगाया कि संसद में सीमित समय मिलने के बावजूद चड्ढा ने बड़े राजनीतिक सवालों की बजाय एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने जैसे छोटे मुद्दों को प्राथमिकता दी। ढांडा ने गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, पश्चिम बंगाल में मतदान अधिकार से जुड़े मुद्दों और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर चड्ढा की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता निडरता के साथ संघर्ष करते हैं और नेताओं से भी उसी प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है। ढांडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सदन में प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ तो उस पर भी राघव चड्ढा ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वाकआउट किया तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया।

जल्द होगी घर ...

ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द उनकी घर वापसी होगी। उमेर अहमद इलियासी ने कश्मीर में हुए बदलाव को *नया कश्मीर* बताया। उन्होंने कहा कि अब यहां विकास बढ़ा है, लोग खुशहाल हैं और पर्यटन में भी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पहले यहां के युवा पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब उनके हाथों में कलम है और वे पढ़ाई कर रहे हैं। यह बदलाव कश्मीर के बेहतर भविष्य की ओर इशारा करता है। इलियासी ने पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जिसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद कुछ समय के लिए पर्यटन पर असर पड़ा था। हालांकि, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कश्मीर जरूर आएं। उनके अनुसार, अब यहां डर का माहौल नहीं है और हालात सामान्य हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि युद्ध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है और यह विनाश का कारण बनता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में शांति स्थापित करने में भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हालात बेहतर होंगे और शांति कायम होगी।

अमेरिका ने माना- ईरान...

कम है। एक स्थानीय ईरानी टीवी चैनल ने लोगों से अपील की कि वे *दुश्मन पायलट* को जिंदा पकड़कर पुलिस को सौंपें। इसके लिए इनाम देने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पायलट को ढूंढने पर करीब 10 अरब तोमन (लगभग 60 हजार डॉलर) का इनाम घोषित किया गया है। ईरान की तसनीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, अमेरिका ने पायलट की तलाश के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और सी-130 हरक्यूलिस विमान लगाए हैं। ये विमान पश्चिमी ईरान में कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने दूसरा एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी मार गिराया है। हालांकि, पहले अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एक एफ-35 मिसाइल हमले के बाद सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल रहा था। एफ-35 दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक है। अगर इसके गिरने और पायलट के पकड़े जाने की पुष्टि होती है, तो यह संघर्ष में बड़ा मोड़ ला सकता है। इस बीच, ईरान ने खाड़ी देशों में हमले तेज किए हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास भी तनाव बढ़ा है। वहीं अमेरिका और इजराइल भी ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें ...

बढ़ती लागत के कारण उनका कारोबार बंद हो सकता है, जिससे देश की आवाजाही और सप्लाई सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। जिओ न्यूज और अन्य मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने गुरुवार देर रात ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने पेट्रोल की कीमत 137.23 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 458.41 रुपए कर दी और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 184.49 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 520.35 रुपए कर दी। मंत्री ने इस बढ़ोतरी का कारण मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा लागत में हो रही वृद्धि को बताया। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम-उर-रहमान ने इस बढ़ोतरी को घोर अन्याय बताया और कहा कि इसका सबसे ज़्यादा असर कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बाइक चलाने वालों, डिलीवरी करने वालों, छात्रों और दिहाड़ी मजदूरों को इस मूल्य वृद्धि का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने पहले पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़ाई थी और अब हालिया संशोधन में 137 रुपए बढ़ा दी है, जो क्रूरता की हद है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) को अरबों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के विशेष सहायक शफी जान ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत 458 रुपए और डीजल 520 रुपए तय करना घोर अन्याय है। उन्होंने ईंधन संकट का कारण संघीय सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों को बताया और कहा कि जनता के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को लाहौर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें जोर देकर कहा गया कि डीजल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के हिसाब से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रही तो ट्रांसपोर्टरों को अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। कराची के ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के प्रेसिडेंट मलिक शहजाद ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए बढ़ती लागत से निपटने के लिए माल ढुलाई के किराए में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बीच, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के बावजूद सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर करने के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। फोरम ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस लेवी को तुरंत खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कारोबारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा यह बोझ अब असहनीय होता जा रहा है।

हेलीकॉप्टर में खराबी ...

कारण रैली रद्द कर दी गई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग न हो पाने के कारण बाद अमित शाह ने लोगों को फोन के जरिए संबोधित किया रैली में शामिल न हो पाने के लिए माफी मांगी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अश्विनी राय सरकार को वोट देने की अपील की, ताकि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत हों सकें। अमित शाह शाह ने चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस में शामिल होने का जनता से वादा किया। बाद में वह अपने अगले कार्यक्रम के लिए पड़ोसी ग्वालपाड़ा जिले के दुधनै के लिए रवाना हुए। इसके बाद अमित शाह ग्वालपाड़ा जिले के दुधनै में अपनी अगली जनसभा के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि गृह मंत्री दो दिवसीय असम दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने कोलियाबर में अगप उम्मीदवार केशव महंत के समर्थन में भी रैली की थी। शुक्रवार को उनकी तीन सभाएं प्रस्तावित थीं, जिनमें कामरूप जिले के पलाशबाड़ी में भी एक सभा शामिल थी। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। दुधनै में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने यहां सिर्फ चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन आदिवासियों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 75 साल में कांग्रेस ने किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया। शाह ने बताया कि 2013 तक आदिवासियों का बजट सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपए था, जिसे पीएम मोदी ने बढ़ाकर 1 लाख 38 हजार करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने आदिवासी संस्कृति, संगीत और कला को विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है।

यूपी एटीएस ने पाकिस्तान ...

आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश को विफल करने में सफलता हासिल की है। एटीएस के अनुसार एक गिरोह पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और उनके निर्देश पर देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। गिरोह का मुख्य काम देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की रेकी कर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेजना और योजनाबद्ध तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।

कांग्रेस घुसपैठ एवं दंगा कराती थी, भाजपा उन्हें निकाल बाहर करती है : योगी आदित्यनाथ

शोणितपुर (हिंस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ एवं दंगा कराने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ऐसा करने वालों को निकाल बाहर करती है। पहले नौजवानों के हक पर घुसपैठिए काबिज होते थे, असम के लोगों का राशन डकार जाते थे, लेकिन अब डबल इंजन सरकार असम के हर नागरिक को उसका हक दिलाने की गारंटी ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम विधानसभा चुनाव में बरछला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ऋतु बरन शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए उपरोक्त बातें कही। उन्होंने जनता से 9 अप्रैल को कमल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली, किसानों का संरक्षण और विदेशी आक्रांताओं को धूल धूसरित करने वाली इस पावन धरा के सामने कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ मिलकर पहचान का संकट खड़ा किया। यह संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था। कांग्रेस व एआईयूडीएफ के अघोषित समझौते के कारण असमिया जाति, माटी एवं बेटी के सामने पहचान का संकट हुआ था। इन्होंने तुष्टिकरण की नीति पर चलकर असमिया पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया। यहां की माटी में घुसपैठियों को घुसाकर असम के सामने पहचान का

संकट खड़ा किया। असम के नागरिकों, बहनों के हक पर घुसपैठियों के जरिये डकैती डलवाई। असमिया संस्कृति मिटाने की साजिश रची, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली और असम में पहले सर्बानंद सोनोवाल, फिर डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तो असम चाय के साथ अब चिप उत्पादन का नया केंद्र भी बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों का राशन घुसपैठिए खा जाते थे। अब असम के लोगों को राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर गरीब को पांच लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा, प्रधानमंत्री आवास, नौजवानों को रोजगार-नौकरी मिल रही है। अब चाय बागान में काम करने वाली बहनों, कारीगरों, नौजवानों के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था है। भाजपा असमिया संगीत-संस्कृति, महापुरुषों, महानायकों, योद्धाओं को सम्मान दे रही है। अब असम में विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय दिख रहा है। मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव कॉरिडोर व भूमि संरक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठ व दंगा कराती थी। असम के लोगों का संरक्षण होगा और एक-एक घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे। कांग्रेस घुसपैठ-दंगा कराती थी और भाजपा ऐसा करने वालों को निकाल बाहर करती है। यूपी की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन वहां 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा है, सब चंगा है। 500 वर्ष में जो काम नहीं हो पाया, वह काम भी अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के रूप में हो गया। उन्होंने कहा कि यूपी में उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद नहीं है, वहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार लव जेहाद, लैंड जेहाद का सफाया करने को संकल्पित है। कांग्रेस व यूडीएफ को घुसपैठियों का वोट चाहिए, वे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकतीं। इन पार्टियों को देश की कीमत पर वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार पूर्वोत्तर भारत में आए हैं, 60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में इतनी बार कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। उन्होंने 11 साल में पूर्वोत्तर भारत की 78 और असम की 36 यात्राएं की हैं, तब शांति, सुरक्षा व सुशासन का माहौल तैयार हुआ है।

असम में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे आनंद मिश्रा

गुवाहाटी (हिंस)। असम-मेघालय कैडर के पूर्व आईपीएस तथा बिहार विधानसभा सदस्य आनंद मिश्रा आगामी दिनों में असम विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आनंद मिश्रा 5 अप्रैल को तिनसुकिया में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी पुलक गोहाईं के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल को वे लखीमपुर में भाजपा उम्मीदवार मानव डेका के पक्ष में प्रचार अभियान चलाएंगे और स्थानीय मतदाताओं से संपर्क साधेंगे। अपने दौरे के अंतिम दिन 7 अप्रैल को आनंद मिश्रा नगांव में आयोजित एक चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे, जहां वे पार्टी के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे।

नितिन नवीन ने कमलपुर में एनडीए उम्मीदवार दिगंत कलिता के समर्थन में किया चुनाव प्रचार

कामरूप (हिंस)। एनडीए के कमलपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिगंत कलिता के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार किया और केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले दस वर्षों से विकास और जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चाय बागान के श्रमिकों को 500 रुपये तक मजदूरी दी जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। पूर्व नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 1962 के दौरान जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनदेखी की थी। उन्होंने कहा कि सही नेतृत्व के निर्णय से ही देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान असम के पारंपरिक गमछा का अपमान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 22 लाख गरीबों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि आगामी भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार चुनाव के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए विकास और सुशासन में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने गुवाहाटी में पूब गुवाहाटी के भाजपा उम्मीदवार दिप्लू रंजन शर्मा के समर्थन में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने का आह्वान किया।

सिलचर में 31 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, एक गिरफ्तार

कछार (हिंस)। सिलचर में भारी मात्रा में हेरोइन के साथ एक तस्कर को बीती देर शाम गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर सिलचर थाना पुलिस की एक टीम ने मादक पदार्थों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर करीब 31 लाख रुपए मूल्य की संदिग्ध हेरोइन बरामद की है। अभियान के दौरान पुलिस ने पांच साबुनदानी में छिपाकर रखी गई कुल 61 ग्राम संदिग्ध हेरोइन अबुल हुसैन चौधरी के कब्जे से बरामद की। गिरफ्तार आरोपी अलुदिंग चौधरी का पुत्र तथा सिलचर थाना क्षेत्र के कनकपुर पार्ट-2 का निवासी है, जिसे उसके किराए के मकान से पकड़ा गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी है। इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पूसीरे की आरपीएफ ने सुरक्षा, संरक्षण और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को किया अधिक सुदृढ़

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सराहनीय प्रदर्शन से यात्री सुरक्षा, संरक्षण एवं जनसेवा के प्रति अपनी सशक्त और निरंतर प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। सघन निगरानी, त्वरित कार्रवाई और सक्रिय प्रवर्तन रणनीति के माध्यम से आरपीएफ ने रेल परिसरों में सुरक्षा को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है, जिससे यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित यात्रा वातावरण सुनिश्चित हुआ है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज बताया है कि उक्त वर्ष के दौरान, पूसीरे की आरपीएफ ने चोरी, दलाली (टाउटिंग) तथा अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलों का अनुसंधान किया, गिरफ्तारियां हुई तथा अवैध टिकट जब्त किए गए। पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई की गई तथा रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा हेतु अतिक्रमण हटाए गए, जो सुरक्षा और संचालन के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को दर्शाता है। प्रवर्तन के साथ-साथ, आरपीएफ ने निरंतर मानवीय पहल भी किए, जिसमें मानव तस्करी के चंगुल से पीड़ितों को रेस्क्यू करना तथा विपत्तिग्रस्त महिलाओं एवं बच्चों सहित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाना शामिल है। अवैध और नशीले सामग्रियों की महत्वपूर्ण बरामदगी भी इसकी सतर्कता को दर्शाती है, जो यात्री सुरक्षा, संरक्षण और रेलवे संचालन की विश्वसनीयता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अपने प्रयासों के तहत, पूसीरे के आरपीएफ ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि के दौरान कुल 2,355 मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए, 1,265 उपकरणों का सफलतापूर्वक पता लगाया गया तथा 291 फोन बरामद किए गए, जिनमें से 264 फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। यह पहल आरपीएफ द्वारा डिजिटल साधनों के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है, जिससे यात्री शिकायतों का समाधान और खोए या चोरी हुई संपत्ति की त्वरित बरामदगी सुनिश्चित हो रही है तथा रेलवे सुरक्षा में जनविश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। उक्त वर्ष के दौरान, आरपीएफ ने यात्रियों के सामान की चोरी के 219 मामले दर्ज किए, जिनमें 285 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। अनधिकृत गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए दलालों के खिलाफ 120 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 128 गिरफ्तारियां हुईं। इन अभियानों में कुल 757 टिकट जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 23 लाख रुपए से अधिक है। जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में पत्थरबाजी की 154 घटनाओं पर कार्रवाई की गई, जिनमें 116 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

चुनाव 26 : मुस्लिम मतदाता एआईयूडीएफ के पक्ष में एकजुट होंगे : असदुद्दीन ओवैसी

गुवाहाटी (हिंस)। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के समर्थन में असम विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान चलाने के लिए असम पहुंचे हैं। ओवैसी आज दूसरे दिन बराक घाटी में चुनाव अभियान में हिस्सा लेते हुए एआईयूडीएफ के समर्थन में मतदाताओं से एकजुट होने का आह्वान करेंगे। ज्ञात हो कि ओवैसी गुरुवार को असम पहुंचे थे। इस दौरान निचले असम के बरपेटा, धुबड़ी आदि जिलों में रात तक धुंआधार चुनाव प्रचार करते हुए दावा किया कि असम में मुस्लिम मतदाता आगामी 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में एआईयूडीएफ के पक्ष में एकजुट होकर वोट डालेंगे। इस बीच एक जनसभा को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और इस क्षेत्रीय पार्टी को राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक शक्ति के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान एकजुट होकर वोट डालेंगे, और बदरुद्दीन अजमल के 29 उम्मीदवार जीतेंगे। असम की राजनीति का फैसला एआईयूडीएफ ही करेगी।

ओवैसी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर *चुप* रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे राजनीतिक माहौल ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एआईयूडीएफ के लिए समर्थन को और मजबूत किया है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियानों पर चिंता जताते हुए, ओवैसी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि अजमल ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर यह वन भूमि है, तो उन्हें कोई दूसरी जमीन दी जाए। अन्यथा, उन्हें वहां से न हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 50 हजार लोगों को बेदखल किया गया है और इसे सिर्फ नफरत की वजह से किया गया एक बड़ा अन्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि असम में अल्पसंख्यक समुदायों को लंबे समय से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक खास मकसद से असम आया हूं। मैं असम में *मियां मुसलमानों* के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने आया हूं। ओवैसी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे मुद्दों से निपटने के तरीके को लेकर भाजपा और पिछली कांग्रेस सरकारों, दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि असम में दशकों से अल्पसंख्यक समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता रहा है। इस समुदाय की नागरिकता के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

असम चुनाव 26 : भाजयुमो के कार्यक्रम में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री

शोणितपुर (हिंस)। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू शुक्रवार को शोणितपुर जिला के ढेकियाजुली में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) द्वारा आयोजित *युवा ही नेतृत्व करेंगे* कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहुंचे। ज्ञात हो कि, ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में 65 नंबर ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार अशोक सिंघल भी शामिल हुए, जिन्होंने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं और उस क्षेत्र के युवाओं से बातचीत की। सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री खांडू ने देश के भविष्य को संवारने में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और कहा कि युवाओं की ऊर्जा और सोच भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं को जिम्मेदारी लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम युवा सोच वाले लोगों से बातचीत करने का एक मंच बना, जहां नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि *युवा शक्ति* की ताकत देश को आगे ले जाने में निर्णायक साबित होगी। ज्ञात हो कि पेमा खांडू असम विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में कई चुनावी सभाओं में अब तक हिस्सा ले चुके हैं।

ट्रेन के अंदर छह साल की बच्ची की हत्या में पिता गिरफ्तार

लखीमपुर (हिंस)। असम के लखीमपुर जिलांतर्गत सिलानिबारी स्टेशन पर एक ट्रेन के अंदर शुक्रवार को छह वर्षीय बच्ची की हत्या उसके पिता ने कर दी। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना सुबह करीब 9.15 बजे 15813 डेकारगांव-मुरकोंगसेलेक एक्सप्रेस के एक जनरल कोच के अंदर हुई। घटना के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। चश्मदीदों के बयान दर्ज करने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, ट्रेन सुबह करीब 10.58 बजे सिलानिबारी से रवाना हो गई। हत्या के पीछे का मकसद पता नहीं चल पाया है। आरोपी और बच्ची के शव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी को सौंप दिया गया है।

धूबड़ी में अगप, बीजेपी और बीपीएफ उम्मीदवार की बैठक आयोजित

धुबड़ी (विभास)। असम गण परिषद पार्टी के धुबड़ी जिला कार्यालय में एनडीए सहयोगी दल के उम्मीदवार उत्तम प्रसाद की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की धुबड़ी विधानसभा बनेंद्र नारायण भट्टाचार्य ने की। भट्टाचार्य के आह्वान पर बैठक में उपस्थित जिला समिति के अध्यक्ष विश्वजीत कलिता ने इस बार चुनाव में असम गण परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बीपीएफ गठबंधन की उम्मीदवार को जीतने के लिए धुबड़ी निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में प्रचार के लिए सुझाव दिया। इसके बाद उत्तम प्रसाद ने अपना बहुमूल्य भाषण दिया और इस बैठक के सुझाव को स्वीकार करते हुए हैं हर संभव सहयोग करने का वादा किया। बैठक में असम गंज परिषद के उपाध्यक्ष अमल कुमार शाह केंद्रीय सदस्य दिलीप दत्ता जिला समिति के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने संक्षेप भाषण दिया।

बंगाईगांव में श्री हनुमान जन्मोत्सव भव्यता के साथ किया गया

बंगाईगांव। श्री हनुमान जन्मोत्सव समारोह समिति के तत्वावधान में शहर में तीन दिवसीय भगवान केसरीनंदन बजरंगबली का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम दिन 31 मार्च को बड़ा बाजार स्थित श्री राम मंदिर के प्रांगण में चौबीस घंटे के अखंड रामायण पाठ से हुआ। द्वितीय दिन 1 अप्रैल को इसी मंदिर परिसर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। भक्ति संगीत और मधुर स्वर में प्रस्तुत चौपाइयों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। कार्यक्रम के उपरांत भगवान हनुमानजी को छप्पन भोग अर्पित किया गया। तृतीय एवं अंतिम दिन 2 अप्रैल को प्रात:काल बजरंगबली का अभिषेक, हवन, पूजन एवं महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधिपूर्वक पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। इसके उपरांत सवामणी प्रसाद का महाभोग अर्पित किया गया। दोपहर में हनुमान

जी की एक विशाल एवं भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। यह शोभायात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर एओसी रोड, पगला स्थान, बीओसी गेट स्थित श्री हनुमान मंदिर से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बंगाईगांव रोलर फ्लोर मिल पहुंची। शोभायात्रा में आकर्षक झांकियां, भजन-कीर्तन, ढोल-नगाड़ों की धुन एवं श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। जगह-जगह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा श्रद्धालुओं विशेषकर श्री शाम अरदास ताली कीर्तन, सालासर भक्त मंडल, मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच, श्रीदेव आइसक्रीम ग्रुप आदि ने शोभायात्रा का स्वागत कर पुष्प वर्षा की और पेयजल, चॉकलेट,आइसक्रीम, प्रसाद आदि वितरण किया। शोभायात्रा का समापन बंगाईगांव रोलर फ्लोर मिल में प्रसाद वितरण के साथ हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रात्रि में तेरापंथ भवन में सवामणी महाप्रसाद (सामूहिक भोजन) का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। तीन दिवसीय कार्यक्रम को सफल करने में सकल मारवाड़ी समाज के सभी सदस्य सक्रिय योगदान रहा। इस सफल आयोजन के लिए श्री हनुमान जन्मोत्सव समारोह समिति की ओर से सभी सदस्यों एवं सहयोगियों को धन्यवाद दिया। दूसरी तरफ बगाईगांव के अन्य मंदिरों में भी इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीओसी गेट स्थित हनुमान मंदिर में भी तीन दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भजन कीर्तन, नृत्य नाटिका, बच्चों में हनुमान चालीसा पाठ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के दिन इस मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहा। मंदिर संचालन समिति ने भक्तों के दर्शन के लिए अनुशासनात्मक सराहनीय व्यवस्था की थी। न्यू बंगाईगांव स्टेशन के पास स्थित श्री गौरीशंकर हनुमान हाथाबाबा मंदिर मे भी दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत श्री हनुमंत जन्मोत्सव उत्सव मनाया गया।

संपादकीय

जंग जारी रहेगी

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीका को संबोधित करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि अभी ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आगामी 2-3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमला किया जाएगा। हम जल्द ही अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। जो जीत हम हासिल कर रहे हैं, दुनिया ने ऐसी जीत कभी नहीं देखी होगी! राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर पुराना मुहावरा दोहराया कि हमने ईरान की वायुसेना, नौसेना, मिसाइल-ड्रोन क्षमताएं नष्ट कर दी हैं। यहां तक कि उसके परमाणु ठिकाने भी तबाह कर दिए हैं। अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। ईरान के सभी बड़े नेता मार दिए गए हैं। यदि ईरान परमाणु बम बना लेता, तो वह अमरीका-इजरायल के लिए मौत साबित होता! दरअसल जो गलतियां पुराने राष्ट्रपतियों ने की थीं, मैं उन्हें ठीक कर रहा हूं। इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध 3 साल 8 माह से अधिक और वियतनाम युद्ध 19 साल से अधिक लड़े गए थे। ईरान युद्ध को अभी 32-33 दिन ही बीते हैं और हमने लगभग लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमरीका युद्ध खत्म करने के बेहद करीब है। हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। गैस उत्पादन में अमरीका 'नंबर वन' है। हमें तेल के लिए होर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं है। जिन्हें तेल-गैस की किल्लत है, जरूरत है, वे खुद होर्मुज जाएं। अलबत्ता हमसे तेल खरीदें, क्योंकि अमरीका के पास बहुत कच्चा तेल है। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय संबोधन का सारांश यह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गौरतलब यह है कि अमरीका ईरान युद्ध पर अभी तक करीब 3.50 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और उसने 200 अरब डॉलर (करीब 19 लाख करोड़ रुपए) का अतिरिक्त बजट मांगा है, लेकिन अमरीकी कांग्रेस फिलहाल उसे पारित करने के मूड में नहीं है। अमरीका का युद्ध पर हररोज का औसतन खर्च 9400 करोड़ रुपए का है। अमरीका में पेट्रोल के दाम 4.06 डॉलर प्रति गैलन के स्तर को छू चुके हैं। इस पर ही हाहाकार मचा है, क्योंकि यह बढ़ोतरी अभूतपूर्व है। ईरान में महंगाई दर 50.6 फीसदी है। यह अकल्पनीय है। अनाज की कीमतें 140 फीसदी और डेयरी उत्पादों की कीमतें 117 फीसदी बढ़ गई हैं। एक किलो चावल के दाम 20 लाख रियाल और दाल की कीमत 35 लाख रियाल है। रोजमर्रा की सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। वस्तुओं की उपलब्धता ही सवालिया है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप का कोई वैश्विक सरोकार नहीं है? इजरायल की अर्थव्यवस्था का तो कचूमर निकल चुका है। वह तो 1.20 करोड़ की आबादी का छोटा-सा देश है। इजरायल को हर हफ्ते 1.6 अरब डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अब जनता सडक़ों पर उतर आई है। यदि भारत का उल्लेख करें, तो करीब 55 लाख भारतीयों को खाड़ी देश छोड़ कर भारत लौटना पड़ा है। दुबई की अति सुरक्षित वाली छवि भी खंडित हुई है। खाड़ी देशों से आने वाले अधिक भारतीय लौट आए हैं। इससे नया आर्थिक संकट सामने होगा। कुवैत से 20 भारतीयों के शव केरलम के कोचिन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाए गए हैं। वे युद्ध और हादसों के शिकार हुए हैं। यह खुलासा विदेश मंत्रालय के सचिव (गल्फ) ने किया है। क्या स्वदेश लौटे भारतीय बेरोजगार हो गए हैं अथवा औने-पौने मेहनताने पर वे भारत में ही काम करने को विवश होंगे? यदि रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत की चर्चा करें, तो मई, 2026 तक भारत सरकार और तेल कंपनियों को कुल 40,484 करोड़ रुपए का घाटा होगा। तेल, एलएनजी, पीएनजी, खाद आदि के घाटे अलग हैं। होर्मुज पर अब भी हमारे 18 जहाज फंसे हैं। यदि ईरान के साथ भारत का व्यापार-सौदा नए सिरे से हो चुका है और ईरान ने 6 लाख बैरल कच्चे तेल का जहाज भारत की ओर रवाना किया है, तो भारत के अपने जहाजों को भी अनुमति दी जानी चाहिए। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन अद्र्धसत्यों और झूठे, फर्जी दावों से भरा था। जिन मुद्दों के आधार पर अमरीका-इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, वे स्थितियां आज भी मौजूद हैं। परमाणु कार्यक्रम अब भी जिंदा और सक्रिय है, हत्याएं और खामेनेई वाली इस्लामी हैं, होर्मुज पर ईरान का कब्जा है, तो फिर हमला क्यों किया गया था? डोनाल्ड ट्रंप की कौनसी बात पर विश्वास किया जाए, कौनसी सच्ची है, वह कभी बोलते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, कभी बोलते हैं कि युद्ध जारी रहेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध 3 साल 8 माह से अधिक और वियतनाम युद्ध 19 साल से अधिक लड़े गए थे। ईरान युद्ध को अभी 32-33 दिन ही बीते हैं और हमने लगभग लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमरीका युद्ध खत्म करने के बेहद करीब है। हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। गैस उत्पादन में अमरीका 'नंबर वन' है। हमें तेल के लिए होर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं है। जिन्हें तेल-गैस की किल्लत है, जरूरत है, वे खुद होर्मुज जाएं। अलबत्ता हमसे तेल खरीदें, क्योंकि अमरीका के पास बहुत कच्चा तेल है। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय संबोधन का सारांश यह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गौरतलब यह है कि अमरीका ईरान युद्ध पर अभी तक करीब 3.50 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और उसने 200 अरब डॉलर (करीब 19 लाख करोड़ रुपए) का अतिरिक्त बजट मांगा है, लेकिन अमरीकी कांग्रेस फिलहाल उसे पारित करने के मूड में नहीं है। अमरीका का युद्ध पर हररोज का औसतन खर्च 9400 करोड़ रुपए का है।

कुछ अलग

पुलिस हमारी जिंदाबाद

हमारे यहां पुलिस का बड़ा महत्त्व है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता आजादी के बाद निरंतर महसूस की गई। आजाद भारत के नागरिकों में स्वाभाविक रूप से एक अराजकता पनपनी थी, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी बढ़ाया जाना लाजिमी तौर पर जरूरी था। पुलिस बल की वृद्धि के साथ ही अपराधियों, हत्यारों, आतंकवादियों तथा बलात्कारियों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। जनता को लगा कि जिस अनुपात से पुलिस बल बढ़ रहा है, उस अनुपात से अपराध नहीं बढ़ रहे, इसलिए ऐसे-ऐसे दिलेर लोग सामने आए, जो पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं थे। बेचारे पुलिस वाले भी हमारी तरह ही थे, सो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। उन्होंने माफिया सरदारों को बुलाया और कहा- 'देखो भाई, हम एक-दूसरे के पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम सांपनाथ तो हम नागनाथ! इसलिए ऐसी तिकड़म करो कि जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके , यानी जनता को तुम भी लूटो और हम भी लूटें। घोड़ा घास से यारी करे तो खाये क्या? इसलिए इसके सिर के तमाम बल पूरी जुगत से लूट लो।' सरदार बोले- 'वाह भाई, हम तो यही चाहते हैं। चोरों के भाई उठाईगीर, नेकी और पूछ-पूछ, सोने पे सुहागा आदि हिन्दी साहित्य के अनेक मुहावरे हम पर एक साथ लागू हो रहे हैं। लेकिन भाई पुलिस जी यह तो बताओ इस मिलीभगत की कुश्ती के कायदे क्या रहेंगे?' पुलिस ने मूंछों पर हाथ फेरकर कहा- 'देखो सरदारों, अपने-अपने क्षेत्रों में आप सब नए से नया कीर्तिमान स्थापित करो।

नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया

पश्चिम बंगाल बढ़ती अराजकता : लोकतंत्र के लिए चुनौती

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक और विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष

चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक और विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

देश दुनीया से

प्रशिक्षकों को नकद ईनाम कब?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों को उनके द्वारा जीते गए पदकों के अनुसार नगद ईनाम दिया, मगर उनके प्रशिक्षकों को इस बार भी नगद ईनाम नहीं दिया गया, जबकि नई खेल नीति में खिलाड़ी के प्रशिक्षक को भी नगद ईनाम का प्रावधान है। खेल विभाग क्यों प्रशिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है? कबड्डी में भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी सहित कई खिलाडियों को कोच रतन ठाकुर ने तराशा है तथा दर्जनों अंतरराष्ट्रीय हैंडबाल खिलाड़ी तैयार करने वाली कोच स्नेह लता क्या वह नगद ईनाम के हकदार नहीं हैं। इसी तरह अन्य खेलों के प्रशिक्षक भी हैं। आज का अभिभावक खेलों में भी अपने बच्चों का कैरियर देख रहा है क्योंकि खेल आज अपने आप में एक प्रोफैशन है। मानव द्वारा विज्ञान में बहुत प्रगति कर प्रौद्योगिकी व चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए सफल शोध कर जीवनशैली को काफी आसान व सुविधाजनक बना लिया है, मगर शिक्षण व प्रशिक्षण में शिक्षक व प्रशिक्षक की भूमिका का महत्व आज भी वही है, जैसा हजारों साल पहले था। महाभारत में कृष्ण सारथी नहीं होते तो क्या अर्जुन भीष्म, कर्ण व अन्य अजेय महारथियों को हरा पाता। विश्व स्तर पर किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का होना बेहद जरूरी होता है। हमारे यहां खेल प्रशिक्षण के लिए वह वातावरण ही नहीं बन पाया है, जिसमें प्रशिक्षक खिलाड़ी से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम दिला सके। खेल प्रशिक्षण दस साल से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाले प्रक्रिया है। इतनी समय अवधि खेल प्रशिक्षण को देकर ही खिलाड़ी अपने प्रदेश व देश को गौरव दिला पाता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं बन पाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रशिक्षकों को कभी विभिन्न विभागों की भर्तियों में ड्यूटी तो कभी मेलों व उत्सवों में हाजिरी भरनी पड़ती है। खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति ही उच्च खेल परिणामों के लिए की गई होती है, मगर यहां पर प्रशिक्षकों को केवल मल्टीपर्पज कर्मचारी बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर प्रशिक्षकों का कार्य उच्च खेल प्रशिक्षण से हट कर अपनी फिटनेस तथा सेना में भर्ती कराने तक सीमित हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मेलों व उत्सवों में किसी और खेल का प्रशिक्षक किसी और ही खेल की प्ले फील्ड में नजर आता है। इसी तरह पुलिस आदि विभागों की भर्तियों में एथलेटिक्स प्रशिक्षकों की ड्यूटी तो समझ आती है, मगर वहां तो हर खेल के प्रशिक्षक को भेज दिया जाता है। विभिन्न सरकारों ने खेल ढांचे में काफी तरक्की भी की है, मगर क्षमतावान प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बारे में हिमाचल में अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। स्तरीय प्रशिक्षकों के बिना उत्कृष्ट प्रदर्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षण से दूर रह कर मौज मस्ती कर

रहा है वह तो खुश रहता होगा, मगर जो सच ही में प्रशिक्षण करवा रहा होगा वह जब कई दिनों तक खेल मैदान से दूर रहेगा तो फिर कौन अभिभावक अपने बच्चे को बिना प्रशिक्षक के मैदान में भेजेगा। हद तो तब हो जाती है जब राज्य में चल रहे खेल छात्रावासों में नियुक्त प्रशिक्षकों की ड्यूटी भर्तियों में लगा दी जाती है और खेल छात्रावास में रह रहे खिलाडियों को भी खेल प्रशिक्षण से दूर कर दिया जाता रहा है। क्या प्रतिभा खोज से चयनित इन अति प्रतिभाशाली खिलाडियों को प्रशिक्षक से कुछ समय के लिए ही सही इस तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूर करना कहां तक उचित है। खेल छात्रावासों में नियुक्त प्रशिक्षकों की ड्यूटी खेल प्रशिक्षण के सिवा और कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आजकल हर शिक्षित मां-बाप के दो और कई जगह तो एक ही बच्चा है, ऐसे में वह उसे उस क्षेत्र में उच्चतम शिखर तक ले जाना चाहता है जिसमें बच्चे की रुचि व उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिभा भी हो। आज का अभिभावक अपने बच्चों के कैरियर की खातिर ही सरकार की मुफ्त शिक्षा सुविधाओं को छोडक़र निजी क्षेत्र की महंगी, मगर अधिक गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है। आज लाखों प्रतिभाशाली विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्थानों में डाक्टर व इंजीनियर बनने इसलिए जमा दो की परीक्षा से कई वर्ष पहले पहुंच रहे हैं। इसी तरह अब खेल क्षेत्र में भी हो रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए खेलों में भी कैरियर तलाश रहा है और इस सबके लिए अच्छी खेल सुविधाओं के साथ-साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षक भी लगातार कई वर्षों तक उसके बच्चों को मिलना चाहिए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता बनने का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इसलिए देश में निजी खेल अकादमियों का चलन भी बढ़ रहा है। गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी के विश्व स्तर के परिणाम सबके सामने हैं। यह सब लगातार अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम का ही नतीजा है। इस समय विभिन्न खेलों के लिए देश में निजी स्तर पर कई अकादमियां शुरू हो चुकी हैं। इन खेल अकादमियों को अधिकतर पूर्व ओलंपियन चला रहे हैं और यहां से अच्छे खेल परिणाम भी मिल रहे हैं। इन अकादमियों में जो विशेष है वह यह है कि यहां उच्च क्षमता वाला प्रशिक्षक लगातार उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के पास आज विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड तैयार हैं। वहां पर या तो प्रशिक्षक हैं ही नहीं और जहां हैं भी वे या तो प्रशिक्षण से बेरुख हैं या उनमें अच्छे स्तर के खेल परिणाम दिलाने की क्षमता ही नहीं है। क्या हिमाचल सरकार उड़ीसा, गुजरात आदि राज्य की तरह उत्कृष्ट खेल परिणाम दिलाने वाले बढिया प्रशिक्षकों को यहां लगातार कई वर्षों के लिए अनुबंधित कर प्रदेश के खिलाडियों को राज्य में ही प्रशिक्षण सुविधा दिला कर खेल प्रतिभा का पलायन क्या रोक नहीं सकती है। इससे प्रदेश में खेल वातावरण बनेगा तो हर खेल प्रशिक्षक प्रेरित होकर चाहेगा कि उस के शिष्य भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इस सबके लिए खेल विभाग व जहां प्रशिक्षक प्रशिक्षण करवा रहा है, वहां उसे सही प्रबंधन दें तथा उनके खिलाड़ी जब पदक जीते तो प्रशिक्षक को भी नई खेल नीति के अनुसार नगद ईनाम देकर प्रेरित करें, ताकि पहाड़ की संतानों को ओलंपिक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अच्छा प्रशिक्षण मिले।

आप का नजरीया

शिमला के पांव

अपने ही पांवों से दूर होता जा रहा है शिमला। दूसरी ओर सवाल यह कि शिमला में विकसित क्या हो रहा। वीआईपी कल्चर, राजधानी की संस्कृति या मैट्रोसिटी के तेवर। हमारी योजना में सील्ड रोड की पैरवी में एक सुरक्षित शिमला देखा जा रहा है। गाडियां शहर के चप्पे पर और गुस्ताख नजर यह कि परमिट बन जाए और बन जाएगा, बस इक रसीद चाहिए। राजधानी के रिस्ट्रक्टेड रोड से गुजरने के लिए पांच हजार और फील्ड रोड के लिए दस हजार की रसीद चाहिए। बिना खर्च किए घुसे तो दस हजार का जुर्माना होगा। काफी अंदाज है इस शहर के, नजरें झुका के चलो। खैर हम अंग्रेजों के सांचे में अपनी इज्जत बचा रहे हैं। कहीं चल रहे हैं, तो कहीं चला रहे हैं। कभी शिमला अपने पांवों पर चलता था, तो शहर की धडक़न में इनसान सरीखा शहर दिखाई देता था। अब न शिमला के बाशिंदे वो रहे और न ही शहर में अपनी छवि रही। ये जो सील्ड रोड हम बना रहे हैं या इन्हें ट्रैफिक से बचा रहे हैं, यह एक सीमा को सीमित करने का अंदाज है। विचार यह करना होगा कि इस शहर के पांव कहां तक खुद चलें, शहर को चलाएं या आगे बढऩे की दिशा बताएं। हम इसे राजधानी मानते हैं, तो विकास का पथ पूरे राज्य की जनता का स्वागत करे, अन्यथा अनावश्यक भीड़ से हटाकर इसके पांव धोने पड़ेंगे। शहर का वीआईपी अंदाज इन्हीं संकरे मार्गों से बड़े ख्वाब देखता है। हर किसी के रास्ते पर अगर सचिवालय की इमारत आ रही है या घर को निकले राही के सफर पर कोई वीआईपी इमारत आ रही है, तो कौन किसे छल रहा है। वे वीआईपी जो बिना परमिट के इन रास्तों के बादशाह हैं या शिमला की अपनी बादशाहत से आम नागरिक बहुत दूर हो गए हैं। शिमला के कई लुक हैं, लेकिन आधुनिक बड़ा विकराल होने जा रहा है। शहर का व्यापार-कारोबार, कॉफी के कप पर सुस्त सी चर्चा और जिंदगी के ठहरे लम्हों का उद्गार करता यह शहर, विश्राम की मुद्रा में दफ्तरों की सत्ता को समेट लेता है। क्या इतना सा इंतजाम शहर की मुद्रा में राजधानी हो जाएगा या हम इस शहर में सत्ता के प्रभाव में जीना चाहते हैं। कहना न होगा कि शिमला शहर का ऐतिहासिक गौरव, पर्वतीय परिवेश, हिल स्टेशन की अमानत और हिमाचल का नजरिया अगर जिंदा रखना है, तो इसके विकास, धरोहर संरक्षण और भविष्य की पैरवी में समीक्षा चाहिए। शिमला अब बोझिल आंखों से खुद को देखता है, तो भीड़ में जनता और वीआईपी नंबर के वाहनों की चिल्ल पौं में बिखर सा जाता है। पर्यटक सीजन के आहत पंजों में छटपटाता है, तो इस शहर की व्यावहारिकता में विकास खोजना होगा। शिमला के साथ वाकनाघाट में एक कर्मचारी नगर बसा दीजिए और जहां राजधानी के कामकाज की संगत बैठा दीजिए। शिमला के तीन से चार प्रवेश द्वार अगर भीड़ नियंत्रण के समाधान बनें, तो बिलासपुर, परवाणू और अपर शिमला से आते वाहनों को शहर से दस किलोमीटर पहले रोक कर, वहां से रज्जु मार्गों के जरिए आगे परिवहन संचालन हो तो शिमला में चलने की कसौटियां भी बदलेंगी। बेशक सरकारें कुछ न कुछ प्रयास करती रही हैं, लेकिन अब राज्य राजधानी विकास एरिया यानी एससीआर (स्टेट कैपिटल रिजन) विकसित करना होगा। इसी संदर्भ में शिमला से बाहर भेजे जा रहे कार्यालयों की भूमिका भी सहायक होगी, लेकिन यह सारी कार्रवाइयां अर्थपूर्ण ढंग से परवान चढनी चाहिएं।

हमारी योजना में सील्ड रोड की पैरवी में एक सुरक्षित शिमला देखा जा रहा है। गाडियां शहर के चप्पे पर और गुस्ताख नजर यह कि परमिट बन जाए और बन जाएगा, बस इक रसीद चाहिए। राजधानी के रिस्ट्रक्टेड रोड से गुजरने के लिए पांच हजार और फील्ड रोड के लिए दस हजार की रसीद चाहिए। बिना खर्च किए घुसे तो दस हजार का जुर्माना होगा। काफी अंदाज है इस शहर के, नजरें झुका के चलो। खैर हम अंग्रेजों के सांचे में अपनी इज्जत बचा रहे हैं। कहीं चल रहे हैं, तो कहीं चला रहे हैं। कभी शिमला अपने पांवों पर चलता था, तो शहर की धडक़न में इनसान सरीखा शहर दिखाई देता था। अब न शिमला के बाशिंदे वो रहे और न ही शहर में अपनी छवि रही। ये जो सील्ड रोड हम बना रहे हैं या इन्हें ट्रैफिक से बचा रहे हैं, यह एक सीमा को सीमित करने का अंदाज है। विचार यह करना होगा कि इस शहर के पांव कहां तक खुद चलें, शहर को चलाएं या आगे बढऩे की दिशा बताएं। हम इसे राजधानी मानते हैं, तो विकास का पथ पूरे राज्य की जनता का स्वागत करे, अन्यथा अनावश्यक भीड़ से हटाकर इसके पांव धोने पड़ेंगे। शहर का वीआईपी अंदाज इन्हीं संकरे मार्गों से बड़े ख्वाब देखता है। हर किसी के रास्ते पर अगर सचिवालय की इमारत आ रही है या घर को निकले राही के सफर पर कोई वीआईपी इमारत आ रही है, तो कौन किसे छल रहा है। वे वीआईपी जो बिना परमिट के इन रास्तों के बादशाह हैं या शिमला की अपनी बादशाहत से आम नागरिक बहुत दूर हो गए हैं। शिमला के कई लुक हैं, लेकिन आधुनिक बड़ा विकराल होने जा रहा है। शहर का व्यापार-कारोबार, कॉफी के कप पर सुस्त सी चर्चा और जिंदगी के ठहरे लम्हों का उद्गार करता यह शहर, विश्राम की मुद्रा में दफ्तरों की सत्ता को समेट लेता है।

दृष्टि कोण

अमरीका के पाखंड की राजनीति

अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में एक अधिनियम पारित किया था जिसे अमरीका अंतरराष्ट्रीय मजहबी स्वतंत्रता अधिनियम कहता है। इस अधिनियम के तहत अमरीका का कहना है कि उसके अतिरिक्त दुनिया भर में मजहबी स्वतंत्रता का रक्षक और कोई दूसरा देश नहीं है। इसके आधार पर मजहब को अमरीकी विदेश नीति का प्रमुख आधार बनाया गया है। इस अधिनियम के आधार पर ही वाशिंगटन ने 'अंतरराष्ट्रीय मजहबी स्वतंत्रता अमरीकी आयोग' का गठन किया हुआ है। यह आयोग एक प्रकार से दुनिया भर में फैले अमरीकी दूतावासों को वहां के देशों की आंतरिक स्थिति में दखलअंदाजी का अधिकार प्रदान करता है। यह आयोग दुनिया भर के देशों के बारे में, अमरीका की विदेश नीति के आधार पर हर साल अच्छे या बुरे होने के प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके आधार पर वह कुछ देशों को 'विशेष चिंता करने वाले देश' घोषित करता है। पिछले दिनों अमरीका ने इस आयोग की सालाना रपट जारी की है जिसमें 2025 का लेखा जोखा देने का दावा किया गया है। इसमें भारत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जाहिर की गई है। भारतीय संसद द्वारा पारित अनेक अधिनियमों को मजहबी स्वतंत्रता में दखलअंदाजी बताया गया है। मसलन अनेक राज्यों के मतांतरण निषेध अधिनियम, गोवध निषेध अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, यूनिफार्म सिविल अधिनियम इत्यादि। अमरीका का मानना है कि भारतीय संसद के ये अधिनियम अमरीका के आईआरएफ अधिनियम 1998 का उल्लंघन करते हैं। इसके अतिरिक्त अमरीका को यह भी दुख है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार कर रही है जिसमें भारत के सभी नागरिकों का इंदराज किया जाएगा। उसका मानना है कि इस रजिस्टर के बन जाने से मुसलमानों और ईसाइयों की मजहबी स्वतंत्रता के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। गोहत्या निषेध प्रावधानों को लेकर भी अमरीका की चिंता बढ़ी हुई दिखाई देती है। उसके लिहाज से इससे भी मुसलमानों और ईसाइयों को अपने मजहबी

क्रियाकलाप करने में दिक्कत आती है। एक दूसरी मजेदार बात का भी जिक्र है। कहा गया है कि भारत में औरंगजेब की कब्र है। उसको लेकर विवाद बढ़ रहा है जिससे मुसलमानों के मजहबी कामों में रुकावट पैदा हो रही है। यानी अमरीका के लिहाज से 2024 से भारत में हालात बहुत बदल गए हैं। साफ तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन चिंता जाहिर करती है कि 2014 से पहले जब परोक्ष रूप से कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी, तब देश ठीक-ठाक चल रहा था। जबसे भाजपा सरकार आई है, तब से देश में उथल पुथल मच गई है। मजहबी स्वतंत्रता को गहरा आघात लगा है। कब्र में औरंगजेब चिंतित है और कब्र के बाहर अमरीका चिंतित है। इस सारे हालात के लिए अमरीका ने तथाकथित दोषी भी ढूंढ लिए हैं। इसमें सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद हैं। इतना ही शायद काफी नहीं था। इसमें भारत सरकार की संस्था रॉ को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का विशेष उल्लेख किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि अमरीका की नजर में भारत की मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार तथाकथित दोषियों में, उसने एक प्रमुख घटक का नाम छोड़ दिया है। वह है भारत की जनता। अमरीका के इस तथाकथित मजहबी स्वतंत्रता के रक्षक आयोग ने यह नहीं कहा कि इस सारे कामों की जिम्मेदार भारत की जनता है, जिसने सोनिया गांधी की पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ही नहीं सौंप दी, बल्कि लगातार सौंपती जा रही है। हैरानी की एक दूसरी वजह भी है।

होटल-रेस्टोरेंट में कोयले के चूल्हे, गैस की किल्लत का असर

भागलपुर (हिंस)। जिले में गैस की किल्लत अब रसोई से निकलकर सीधे बाजार तक पहुंच गई है। इसका सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर देखने को मिल रहा है। जहां आधुनिक किचन अब फिर से पुराने दौर की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर की कमी ने मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि अब कोयले के चूल्हे पर मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। धुएं और धीमी आंच के बीच काम करना मजबूरी बन गया है। रेस्टोरेंट के स्टाफ बताते हैं कि गैस नहीं मिलने की वजह से वे पहले जितनी मिठाइयां नहीं बना पा रहे हैं। उत्पादन घट गया है और ग्राहकों की मांग पूरी करना चुनौती बन गई है। वहीं व्यवसायियों का कहना है कि अगर जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो स्वाद के साथ-साथ कारोबार पर भी इसका कड़वा असर और गहराता जाएगा।

राघव चड्ढा ने आपा हाईकमान पर दागे सवाल, कहा

मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है

चंडीगढ़ (हिंस)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाए जाने से आहत सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सवाल दागे हैं। आआपा ने राज्यसभा सचिवालय से राघव के स्थान पर अशोक मित्तल को नियुक्त करने की सिफारिश की है। मित्तल जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। पंजाब में वर्ष 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राघव आआपा का प्रमुख चेहरा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह पंजाब की राजनीति से दूर हैं। राघव चड्ढा ने आज सुबह एक वीडियो जारी किया। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं, *खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। मुझे जब-जब बोलने का मौका मिलता है तो मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता हूं। संसद में ऐसे मुद्दों पर बोलता हूं जिन्हें आमतौर पर सदन में उठाया नहीं जाता।* उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दों पर बात करना अपराध है। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर

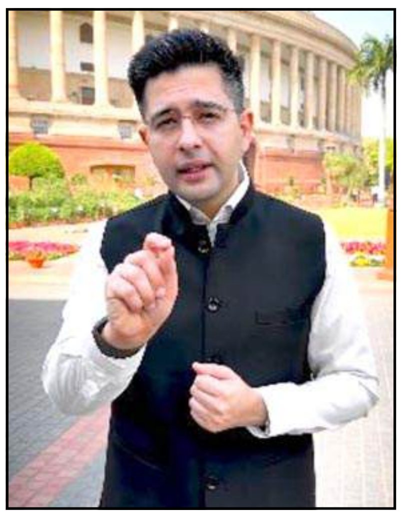

दी ? चड्ढा ने कहा कि यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह लिखकर दिया है कि राघव चड्ढा के सदन में बोलने पर रोक लगा दी जाए। बोलने का मौका न दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा। मैं जब बात करता हूं तो देश के आम आदमी की बात करता हूं। संसद में एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, टोल व बैंक लूट का मुद्दा उठाया। मिडिल क्लास से हो रही लूट, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं आदि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दे उठाने के बाद आम आदमी का फायदा हुआ लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ। मेरी आवाज को कोई क्यों बंद करना चाहेगा। आप लोग मुझे असीमित प्यार देते हैं। मेरा हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे ही मेरा हाथ और साथ थामे रखिएगा। छोड़िएगा मत। मैं आप से हूं, आपके लिए हूं। जिन लोगों ने संसद में बोलने का हक छीन लिया उनके लिए कहना चाहूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।

चार मई को बंगाल से टीएमसी गई : केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज (हिंस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है और 2027 के विधानसभा चुनाव को पूरे दम पर और अपनी पूरी ताकत से जीत दर्ज कर एक इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में ममता का बम नहीं फटेगा और वह फुस्स हो जाएगी, 4 मई को टीएमसी गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल में अराजकता का माहौल बना हुआ है, वह आम जनमानस के लिए खतरनाक है और इसलिए ममता सहित सभी सहयोगी पार्टियों को अब टाटा करने का वक्त आ चुका है और 4 मई का रिजल्ट यह पूरी तरीके से साफ कर देगा। बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और बंगाल में भी सुशासन व्याप्त होगा। अखिलेश यादव द्वारा अधिकारियों को धमकाये जाने वाले मामले पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अखिलेश यादव का पूरा कुनबा जब तक एक गाड़ी में बैठकर सैफई नहीं पहुंच जाता तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय सिविल लाइन में आयोजित जिला गंगापार, यमुना पार और महानगर प्रयागराज के नवनियुक्त जिले के पदाधिकारियों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मानित किया और उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाना है। याद रहे कोई कार्यकर्ता छूटने न पाए और न टूटने पाए। जिस कार्यकर्ता को जिले में जिम्मेदारी नहीं मिली हैं उन्हें आगे कहीं न कहीं समायोजित किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में काम की कोई कमी नहीं है हम सब मिलकर 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाना है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाज को जात-पात पर बांटना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित समाज का त्रिवेणी का पवित्र संगम है। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मिलकर मनाएं और पार्टी को और मजबूती प्रदान करें। क्योंकि पार्टी है तो सरकार है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस अवसर पर महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष बीके सिंह, विधायक राजमणि कोल, गंगापार जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, अमर नाथ यादव, राजेश केसरवानी, डॉ. शैलेश पांडे, कुंज बिहारी मिश्रा, श्याम चंद्र हेला, रमेश पासी, मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी, शोभिता श्रीवास्तव आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

खालसा सिरजना दिवस से पहले खोला जाए करतारपुर साहिब कॉरिडोर : एसजीपीसी

चंडीगढ़ (हिंस)। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने केंद्रीय सरकार से खालसा सिरजना दिवस से पहले करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत खोलने की मांग की है, ताकि सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा कर सकें। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह ने कहा कि समिति का रुख स्पष्ट है और कॉरिडोर को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब क्रिकेट संबंध बहाल किए जा सकते हैं, तो धार्मिक संबंध क्यों नहीं? एसजीपीसी ने 28 मार्च को अपनी वार्षिक बजट सत्र में कॉरिडोर खोलने की औपचारिक मांग रखी थी और सरकार को राजनीतिक संघर्षों से अलग धार्मिक तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया। कॉरिडोर लगभग 4.6 किलोमीटर लंबा है और यह पाकिस्तान के नरवां जिले स्थित करतारपुर साहिब (दरबार साहिब) को भारत के डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। दिल्ली स्थित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसएमसी) के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख सलाहकार परमजीत सिंह चंदोक ने कहा कि सरकार को सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के लिए इस खालसा सिरजना दिवस (13 अप्रैल) को कॉरिडोर खोलना चाहिए। इससे दोनों देशों के लिए व्यवस्था करना आसान होगा। कॉरिडोर मई 2025 से भारतीय पक्ष से सुरक्षा कारणों से बंद है, जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई। जबकि पाकिस्तान ने अपनी सीमा खुली रखी, भारतीय पक्ष से यात्रा अभी भी बंद है।

कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान को लेकर पूर्व सीएम गहलोत का सरकार पर निशाना

जयपुर (हिंस)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म *एक्स* पर अपनी सीरिज इंतजारशास्त्र के चैप्टर 12 के तहत पोस्ट कर इसे लोकतांत्रिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण संस्थान बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। गहलोत ने अपनी पोस्ट में कहा कि कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं

उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि यह स्थान प्रदेश के बुद्धिजीवियों, लेखकों और जनप्रतिनिधियों के लिए एक साझा मंच के रूप में तैयार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार की *बदला लेने की राजनीति* के कारण इस महत्वपूर्ण संस्थान की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि निर्माण पूर्ण होने के बावजूद क्लब को लगभग एक साल तक बंद क्यों रखा गया। साथ ही, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि खुलने के बाद भी इसकी सदस्यता प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू क्यों नहीं की जा रही। गहलोत ने कहा कि क्या सरकार लोकतांत्रिक चर्चा और संवाद से घबरा रही है? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के संसाधनों की बर्बादी और नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा।

न्यायिक आयोग गठित करके की जाए कुलपतियों से जुड़े घोटालों की जाच : संपत

हिसार (हिंस)। इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व मंत्री संपत सिंह ने वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त सभी वर्तमान एवं पूर्व कुलपतियों से जुड़े कथित घोटालों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। हरियाणा सरकार द्वारा तीन वर्तमान एवं एक पूर्व कुलपति के विरुद्ध कथित अनियमितताओं और वित्तीय कुप्रबंधन की जांच के लिए विजिलेंस जांच के आदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामले *हिमखंड का केवल ऊपरी हिस्सा* मात्र हैं। संपत सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि वर्ष 2014 के बाद से सरकार द्वारा नियुक्त कई कुलपतियों पर धन के दुरुपयोग, नौकरियों की बिक्री, पक्षपात तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने इन आरोपों पर समुचित संज्ञान नहीं लिया है। संपत सिंह ने कहा कि यद्यपि एडीजीपी अरशिंदर सिंह चावला एक सक्षम अधिकारी हैं, किंतु इस मामले की व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए एक बड़े स्तर की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से युक्त न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की और कहा कि केवल चार कुलपतियों तक जांच सीमित रखने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि कथित अनियमितताओं का दायरा काफी व्यापक है। अपने शिक्षकीय पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई कुलपतियों ने अपने कार्यकाल के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां कर विश्वविद्यालयों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कई कुलपतियों पर अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं।

जोधपुर नगर निगम : जनगणना में लगाई मृतकों की ड्यूटी

जोधपुर (हिंस)। नगर निगम प्रशासन ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसका खुलासा होने पर हर कोई अचंभित है। नगर निगम ने जनगणना कार्य में मृतकों और डेढ़ साल पहले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। दरअसल गत 27 मार्च को कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी और निगम कमिश्नर सिद्धार्थ पालानीचामी ने 2084 लोगों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें जनगणना के लिए ड्यूटी लगाई गई। इस लिस्ट में जिन लोगों का निधन हो चुका है या जो रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम भी हैं। लिस्ट में एक नाम अब्दुल वाहिद है। उनका जोधपुर के लाला लाजपत राय कॉलोनी में घर है। गत 10 मई 2024 को अब्दुल वाहिद का निधन हो गया था। वे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में यूडीसी थे। चौंकाने वाली बात ये है कि 15 मई 2024 को नगर निगम की ओर से ही मृत्यु प्रमाण-पत्र भी जारी किया जा चुका है। वहीं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की पेंशनर्स कमेटी के संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि वह अगस्त 2024 में विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बावजूद उनकी ड्यूटी जनगणना में लगा दी गई। उन्होंने बताया कि वीरम राम का नाम भी इस लिस्ट में है। वह स्वयं वीरम राम और मुनाराम एक ही दिन रिटायर हुए थे। लेकिन पूरी लापरवाही है कि सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई। इसी तरह रामापीर कॉलोनी निवासी दीपक अवस्थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में यूडीसी थे। उनका निधन 13 फरवरी 2026 को हो गया था। उनका भी लिस्ट में नाम है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारी मौन साधे बैठे है। वहीं आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी तबादला ऑर्डर के चलते रिलीव हो गए।

कंपनी में इंवेस्टमेंट के नाम पर 6 करोड़ की धोखाधड़ी

स्थानीय पीड़ित ने कई लोगों से धन लेकर निवेश कराया

जोधपुर (हिंस)। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 18 ई में रहने वाले व्यक्ति से कुछ लोगों ने एक कंपनी में इंवेस्टमेंट के नाम पर बड़ा मुनाफा और एजेंट के तौर पर काम करने का प्रलोभन देकर पांच- छह करोड़ का फ्र ॉड कर दिया। पीड़ित ने अदालत की शरण लेकर अब महामंदिर थाने में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने घटना में अब अग्रिम पड़ताल आरंभ की है। मामले में रमेश पुरी पुत्र भीमपुरी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टी प्रपोज कॉपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड एवं समृद्ध जीवन फुड्स इण्डिया लिमिटेड के डायरेक्टर महेश किशन मोतेवार और अन्य पर आरोप लगाया गया है। वैशाली मोतेवार, राजेश पंडूरंग, विनोद डांगी, राजस्थान यूनिट हैड, निवासी-गांव बीबीसर जिला झुन्झुनु, राजेश मात्रे निवासी- पुणे, प्रभाद: पारसबार घनश्याम, जस भाई, सोमनाथ, अरूण भालेराव पारसवार, लीला महेश मोतेवार, अभिषेक मोतेवार एवं राजेश को भी नामजद किया गया है। पीड़ित ने बताया कि विनोद डांगी नाम के व्यक्ति ने मेरे व मेरे अन्य साथियों से सम्पर्क कर बताया कि वह समृद्ध जीवन फुड्स इण्डिया लिमिटेड व समृद्ध जीवन मल्टी प्रपोज कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड़ जिसका ऑफिस मैन पावटा सनसिटी अस्पताल, जोधपुर के पास रखा तथा इसका मुख्यालय पुणे में है। कंपनी भारत में करीब 16 राज्यों में हर तरह का व्यवसाय करती है तथा उसका काफी अच्छा मुनाफा देती है। आप भी हमसे जुड़ों और अपना निवेश करों व एजेंट के रूप में अन्य लोगों का निवेश कराओं, जिस पर मैं व मेरे अलावा कुशालाराम सोलंकी, हनुमानाराम, सुनन्दा बोराणा, कैलाश राव, प्रेमाराम, रूपाराम, पूजा बोराणा व रमेश पूरी हम सब उनसे मिलने उनके पावटा ऑफिस गए।

पीडीए की बात सिर्फ दिखावे के लिए करती है सपा : ओम प्रकाश राजभर

जौनपुर (हिंस)। यूपी के जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शुक्रवार को भाग लेने पहुंचे सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने डाक बगले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा में शामिल मुस्लिम नेताओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वे अखिलेश यादव से यह कह सकें कि अगली बार किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति विरोधाभासों से भरी है। उन्होंने कहा कि *मारने वाले और मार खाने वाले एक ही दल में शामिल हो गए हैं,* जिससे पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं, लेकिन सपा की रणनीति कमजोर दिखाई दे रही है। दादरी को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव के निर्णय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने गलत जगह का चयन किया। राजभर के अनुसार, अखिलेश यादव के शासनकाल में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिससे आज भी नाराजगी बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस वर्ग को जोड़ने के लिए अखिलेश प्रयास कर रहे हैं, वहां भी उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी करते

हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कभी मस्जिद में नमाज पढ़ते नजर आते हैं, लेकिन राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाते और मथुरा जाने से भी बचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की बात सिर्फ दिखावे के लिए करती है। राजभर ने यह भी कहा कि सपा सरकार के दौरान आरक्षण को नुकसान पहुंचाया गया और महापुरुषों के नाम पर चल रही योजनाओं को बंद किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अब न दलितों, न पिछड़ों और न ही मुसलमानों का भरोसा जीत पा रही है। साथ ही राजभर ने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और आने वाले चुनाव में सही निर्णय लेगी।

आआपा पर अकाली दल की योजनाओं को अपना बताकर गुजरात में झूठा प्रचार करने का आरोप

संगरूर (हिंस)। शिरोमणि अकाली दल के हलका इंचार्ज एवं पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार को झूठे प्रचार पर घेरते हुए कहा है कि पार्टी के नेता गुजरात में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान अकाली दल सरकार के समय में शुरू की गई योजनाओं को अपना बताकर वहां के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अरविंद खन्ना निकवटर्ती गांव घराचों, रामगढ़, रसालदार छन्नां, महसमपुर, रोशनवाला में अकाली दल की मजबूती के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात में भगवंत मान ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने हर 4 किलोमीटर पर मंडियां स्थापित की है और वह गुजरात में भी ऐसा ही करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा करके झूठ को तूल देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों का उसी तर्ज पर मुफ्त बिजली की सुविधा देगी जैसा कि उनकी पार्टी ने पंजाब में किया है। वह गुजरात में यह भी घोषणा कर रहे हैं कि उन्होने पंजाब में महिलाओं को 1000 रूपया महीना देना शुरू कर दिया है, जबकि यह योजना अभी तक लागू भी नही हुई है। खन्ना ने कहा कि पंजाब में मंडियों की स्थापना तथा किसानों को मुफ्त बिजली योजना पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने शुरू की थी। अकाली दल के बाद सत्ता में आई सरकारों ने इन योजनाओं को बंद करने तथा कटौती करने जैसी घिनौनी चाल चली है। अरविंद खन्ना ने कहा कि आज अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि केंद्र तथा पंजाब की मौजूदा सरकार मिलकर फिर से किसानों का मुफ्त बिजली योजना में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की धोखाधड़ी अब पंजाब में काम नही आएगी। सभी को एहसास हो गया है कि यह सरकार लोगों के लिए बुनियादी स्तर पर कुछ न करके केवल विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। अरविंद खन्ना ने मिल्कफेड वेरका मिल्क पाउडर घोटाले में कुछ जुनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके मामले को दबाने की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय सेना को मिल्कफेड द्वारा आपूर्ति किए गए पूरे दूध के पाउडर को अस्वीकार किए जाने की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। इस मामले में सरकार में बैठे कई चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि पंजाब में सहकारिता मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास है, इसीलिए उनसे अपने खिलाफ जांच सही जांच कराने की उम्मीद नही की जा सकती।

धौलपुर में श्रद्धा और उल्लास से निकाली हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा

धौलपुर (हिंस)। रामभक्त हनुमान के जन्मोत्सव पर गुरुवार रात को धौलपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंडबाजों से सुसज्जित शोभा यात्रा में पौराणिक प्रसंगों पर सजी झांकियों ने मन मोहा। शोभा यात्रा में रामभक्त हनुमान का डोला आकर्षण का केंद्र रहा। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार रात को आगरा मुंबई नेशनल हाईवे स्थित सती वाले हनुमान मंदिर से शोभायात्रा शुरू हुई। हनुमान जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष कुक्ककू शर्मा सहित अन्य ने वैदिक रीति से पूजा अर्चना के बाद में शोभा यात्रा को रवाना किया। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्मध्वजा लिए श्रद्धालु चल रहे थे। शोभा यात्रा में तथा पांच चार दर्जन झांकियां और डेढ दर्जन बैण्ड और ढोल और तासे शामिल रहे। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में भगवान मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम, हनुमान, मां काली, मां दुर्गा, खाटू श्याम, भगवान शिव एवं पार्वती, सीता वनवास, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कालिया नाग का मर्दन तथा राम दरबार सहित विभिन्न पौराणिक प्रसंगों पर झांकियां सजाई गईं थीं। शोभा यात्रा का आकर्षण अंत में चल रहा वीर हनुमान का प्राचीन डोला रहा। हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा महात्मानंद की बगीची, फूटा दरवाजा, हास्पीटल रोड, जगन तिराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, धूलकोट, संतर रोड, तोप तिराहा, बजरिया एवं गडरपुरा होते हुए सती वाले हनुमान मंदिर पंहुचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा के स्वागत के लिए शहर में दर्जनों स्वागत द्वारा बनाए गए तथा जलपान, शर्बत, दूध, पूडी सब्जी तथा आईसक्रीम से भक्तों का स्वागत किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित शोभा यात्रा के दौरान जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी तथा पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित अन्य अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। हनुमान जन्मोत्सव तथा शोभा यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रात भर जयंती के आयोजन तथा सुरक्षा इंजामों का जायजा लेते रहे।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तीन दिवसीय मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ

सहरसा (हिंस)। देश की आर्थिक राजधानी व मायानगरी मुंबई में शुक्रवार को शुभ सीता फाउंडेशन द्वारा तीन दिवसीय मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। जिसमें सहरसा, सुपौल सहित कई जिले के साहित्यकार उपस्थित हुए। समारोह में कार्यक्रम संयोजिका मनोरमा झा, साहित्यकार विनोदानंद झा, अरविंद कुमार अक्कू, प्रो विद्यानंद झा, प्रोकमलानंद झा, तारानंद वियोगी, विभा रानी, कार्तिकेय मैथिल, विनोद कुमार झा सहित अनेकों मैथिली भाषा सेवी व साहित्यकार उपस्थित रहे। औपचारिक उद्घाटन से पहले पिछले तीन वर्षों में दिवंगत हुए मैथिली साहित्यकार को मोन पाड़य छी सत्र में उनके कृतित्व पर चर्चा कर श्रद्धांजलि दी। मैथिली साहित्यकारों में श्रद्धांजलि देने वाले में केदार कानन, विभा रानी, अरुणाभ सौरभ, तारानंद वियोगी, चंद्रेश शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान मैथिली साहित्य मे एआई के प्रभाव के संदर्भ लेखन, अनुवाद व प्रकाशन विषय पर वक्ता प्रदीप बिहारी, कार्तिकेय मैथिल, मनीष ठाकुर, कुमार विक्रमादित्य, राजेंद्र झा और संचालक भास्करानंद झा ने अपने विचार व्यक्त कर अमूल्य सुझाव दिए। तीन दिनों तक मैथिली भाषा व साहित्य पर गंभीर चिंतन और मंथन में देश विदेश के 100 से ज्यादा मैथिली साहित्यकारों काजमावड़ा देश की आर्थिक राजधानी में हुआ है।

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र 13 को बुलाया

चंडीगढ़(हिंस)। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र 13 अप्रैल को सोमवार सुबह 11 बजे पंजाब विधान भवन, चंडीगढ़ में बुलाया है। यह सत्र पहले 16 मार्च को अनिश्चित समय के लिए स्थगित किया गया था। स्पीकर ने विधायकों से प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नियमों का पालन करने और सत्र में अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया है। सत्र के दौरान सरकार और विधायक नए प्रस्तावों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि, विधानसभा सचिवालय ने सत्र का कोई औपचारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन इस सत्र में सरकार की ओर से बेअदबी बिल पेश किए जाने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विशेष रूप से इस दिन धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है।

क्या दवाओं पर ट्रंप के 100प्रतिशत टैरिफ से भारत पर भी असर, नए फैसले से कितना प्रभावित होगा फार्मा सेक्टर

नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सप्लाई चेन जोखिमों का हवाला देते हुए, पेटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय सेक्शन 232 जांच के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य दवा आपूर्ति में विदेशी निर्भरता को कम करना है।

जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से रखा गया बाहर – हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि जेनेरिक दवाओं को फिलहाल इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कंपनियों की प्रमुख ताकत माने जाने वाले जेनेरिक ड्रग्स पर अभी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इससे भारत से अमेरिका को होने वाले सस्ते दवाओं के निर्यात पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा अमेरिकी जेनेरिक बाजार पर निर्भर है और इस छूट से अल्पकाल में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी के अनुसार, भविष्य में जेनेरिक उत्पादन की स्थिति की समीक्षा कर टैरिफ नीति में बदलाव किया जा सकता है।

भारत के लिए क्या चुनौती – हालांकि, लंबे समय में यह फैसला भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पेटेंटेड दवाओं और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स पर भारी टैरिफ से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिसमें भारतीय कंपनियां अहम भूमिका निभाती हैं। खासकर कान्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंटरमीडिएट सप्लाई के क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है।

कंपनियों को लेकर ट्रंप प्रशासन का क्या रुख – अमेरिकी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों के पास अमेरिका में उत्पादन शिफ्ट करने की योजना नहीं होगी, उनके भारत से आयातित पेटेंटेड उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क लागू होगा। हालांकि, जो कंपनियां उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध होंगी, उन्हें शुरुआती राहत के तौर पर 20 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, जो चार साल में बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा।

कैसे लागू होगा टैरिफ – यह टैरिफ जुलाई और सितंबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में अमेरिका में वितरित लगभग 53 प्रतिशत पेटेंटेड दवाएं विदेशों में बनती हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी

नई दिल्ली। पश्चिम एशियामें जारी भारी तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे है लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार 3 अप्रैल को भी देश में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि इस राहत के पीछे तेल कंपनियों को भारी आर्थिक चोट सहनी पड़ रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें इस हफ्ते 115 डालर प्रति बैरल के पार निकल गई थी। होर्मुज जलडमरूमध्य जहां से दुनिया का 20 फीसदी तेल गुजरता है वहां सप्लाई बाधित होने के डर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी अस्थिरता है। इसके बावजूद भारत सरकार और तेल कंपनियों ने घरेलू कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है ताकि आम जनता को महंगाई का झटका न लगे। प्रमुख शहरों में शुक्रवार को भाव इस प्रकार हैं- नई दिल्ली पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर, मुंबई डीजल 103.54 रुपए प्रति लीटर, डीजल 90.03 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता पेट्रोल 105.45 रुपए प्रति लीटर, डीजल 92.02 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई डीजल 100.80 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल 92.39 रुपए प्रति लीटर, बेंगलुरु पेट्रोल 102.92 रुपए प्रति लीटर, डीजल 90.99 रुपए प्रति लीटर एवं लखनऊ पेट्रोल 94.65 रुपए प्रति लीटर, डीजल 87.76 रुपए, पोर्ट ब्लेयर पेट्रोल 82.46 रुपए प्रति लीटर, डीजल 78.05 रुपए प्रति लीटर है।

1.39 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की बिक्री दर्ज

नई दिल्ली। भारत में 27 मार्च तक करीब 1.39 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी अवधि के 1.31 लाख यूनिट्स से अधिक है। मौजूदा रफ्तार जारी रही तो यह आंकड़ा जल्द ही 1.45 लाख यूनिट्स के रिकार्ड को पार कर सकता है। साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में मिलने वाले आफर्स, सरकार द्वारा सब्सिडी को जुलाई 2026 तक बढ़ाना और कंपनियों के डिस्काउंट ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया है। इस ग्रोथ में टीवीएस मोटर कंपनी सबसे आगे रही, जिसने वित्त वर्ष 2026 में 3.3 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर नया मुकाम हासिल किया। बजाज आटो ने 2.76 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जबकि अथेर एनर्जी ने करीब 2.3 लाख यूनिट्स के साथ अपनी स्थिति मजबूत की। वहीं हीरो मोटोकार्प ने शानदार उछाल दिखाते हुए अपनी बिक्री तीन गुना बढ़ाकर 1.39 लाख यूनिट्स तक पहुंचा दी। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक के लिए यह साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसकी बिक्री में गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2026 में ईवी टू-व्हीलर की बिक्री 13.5 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से करीब 17 प्रतिशत ज्यादा है।

मारुति सुजुकी ने वित्तीय वर्ष 2026 में हासिल की रिकार्ड बिक्री

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2026 में मारुति सुजुकी ने रिकार्ड बिक्री हासिल की है। इस दौरान मारुति सुजुकी ने कुल 24.22 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। कंपनी लगातार तीसरे वर्ष 20 लाख यूनिट्स से अधिक की वार्षिक बिक्री पार करने में सफल रही है। मार्च 2026 में कंपनी की कुल बिक्री 2,25,251 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष के मार्च महीने की तुलना में 16.7 प्रतिशतकी बढ़ोतरी दर्शाती है। पिछले वर्ष मार्च में कंपनी ने 1,92,984 यूनिट्स बेची थीं। घरेलू बाजार में मार्च की बिक्री 1,69,428 यूनिट्स रही, जबकि अन्य ओईएम को 8,783 यूनिट्स की आपूर्ति की गई। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला, जो साल-दर-साल आधार पर करीब 42.68 प्रतिशत बढ़ा है। एफवाय26 के दौरान कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में भी स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। एसयूवी सेगमेंट में मारुति की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही ब्रेजा, ग्रांड विटारा, फ्रोंक्स और इरटिगा जैसे माडल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार पर भी जोर दिया, खासकर गुजरात और खरखोदा प्लांट्स में प्रोडक्शन बढ़ा है। मारुति सुजुकी भारतीय आटोमोबाइल उद्योग की लीडर बनी हुई है।

भारत में पहली स्वदेशी गैसीकरण परियोजना के जमीन पट्टे पर समझौता हुआ

25,000 करोड़ की मेगा परियोजना

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव व वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में उतार-चढ़ाव के दौर में भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए, पहली स्वदेशी गैसीकरण परियोजना के जमीन पट्टे पर समझौता हुआ। भारत कोल गैसिफिकेशन ऐंड केमिकल लिमिटेड (बीसीजीसीएल) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने समझौता किया। इसके तहत ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की पहली स्वदेशी परियोजना के लिए समझौता हुआ। इससे आयात पर निर्भरता भी घटेगी। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना की क्षमता 2,000 टन प्रतिदिन (टीपीडी) है। परियोजना के लिए अनुमानित निवेश करीब 25,000 करोड़ रुपये है। यह समझौता महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कोयला गैसीकरण तकनीक कोयले को सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में बदलती है। फिर सिनगैस से अमोनिया, मेथनाल, यूरिया, हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), पेट्रोकेमिकल्स और तरल ईंधन सहित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इस क्रम में लखनपुर परियोजना विशेष रूप से अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह प्रमुख औद्योगिक रसायन है और इसका उपयोग उर्वरकों और खनन में व्यापक रूप से होता है। दरअसल, कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा उत्पादों के आयात को कम करने के लिए सात कोयला परियोजनाओं के लिए 64,000 रुपये मंजूर किए हैं। इन सात परियोजनाओं में से एक लखनपुर परियोजना है। इस क्रम में सात परियोजनाओं में से चार महाराष्ट्र, दो ओडिशा और एक पश्चिम बंगाल में होगी। लखनपुर परियोजना एमसीएल की 350 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित की जाएगी। दरअसल, कोयलना मंत्रालय ने हाल ही में नीति में बदलाव किए हैं। इसके तहत कोयला युक्त क्षेत्र में गैसीकरण परियोजना की अनुमति दी गई है। इस नीतिगत बदलाव से लखनपुर परियोजना को प्रोत्साहन मिला।

तेल संकट गहराया, भारत में कीमतें 4 साल के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है, जिसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय आयल बास्केट की औसत कीमत मार्च 2026 में 113.49 डालर प्रति बैरल पहुंच गई, जो पिछले चार वर्षों का उच्चतम स्तर है। इससे पहले रसिया-यूक्रेन वार के दौरान मार्च 2023 में यह 112.87 डालर तक गई थी। रविवार को ओपेक देशों की बैठक होगी। इसमें आयल प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। 1 अप्रैल को भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की कीमत 120.84 डालर प्रति बैरल दर्ज की गई, जबकि ब्रेंट क्रूड करीब 107 डालर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 से 120 डालर प्रति बैरल के दायरे में बनी हुई हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 100 से 120 डालर प्रति बैरल के दायरे में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है। स्ट्रेट आफ होर्मुज में बाधा आने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है, क्योंकि दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल का ट्रांजिट इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती और रूस में ड्रोन हमलों से सप्लाई और कमजोर हुई है।

कई नए प्रोडक्ट लान्च करने की तैयारी में एमजी

नई दिल्ली

भारतीय बाजार में एमजी मोटर कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2026 में कई नए प्रोडक्ट लान्च करने की तैयारी में है। भारत में कंपनी वुलिंग स्टारलाइट 560 के रीबैज्ड वर्जन को पेश कर सकती है। इस एसयूवी के पेटेंट दाखिल होने और टेस्टिंग के दौरान इसके माडल्स देखे जाने से इसके लान्च की संभावना और मजबूत हो गई है।

डिजाइन की बात करें तो वुलिंग स्टारलाइट 560 का एक्सटीरियर इंटरनेशनल माडल जैसा ही नजर आता है। इसका बाक्सी प्रोफाइल, शार्प लाइटिंग, मेश पैटर्न ग्रिल और मजबूत बंपर इसे आकर्षक बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में चौकोर व्हील आर्च, रूफ रेल्स और ब्लैक-आउट पिलर्स दिए गए हैं, जबकि पीछे की ओर रैपअराउंड टेललाइट्स और स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिलता है। 4,745 मिमी लंबाई और 2,810 मिमी व्हीलबेस के साथ यह एसयूवी फैमिली यूजर्स के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। इंजन और परफार्मेंस के मामले में यह एसयूवी कई विकल्पों के साथ आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका पेट्रोल, प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और पूरी तरह इलेक्ट्रिक वर्जन उपलब्ध है। पेट्रोल इंजन 177 पीएस की पावर देता है, जबकि पीएचईवी वर्जन में कुल आउटपुट करीब 200 पीएस तक पहुंचता है और इसकी कुल रेंज 1100 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं, इलेक्ट्रिक वर्जन 500 से 540 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है, जो इसे लंबी दूरी के लिए भी उपयोगी बनाता है। फीचर्स की बात करें तो इसका इंटीरियर मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आता है, जिसमें 12.8 इंच की टचस्क्रीन, 4जी कनेक्टिविटी, ओटीएस अपडेट और स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और आरामदायक सीटिंग जैसे फीचर्स इसे प्रीमियम बनाते हैं। कीमत को लेकर अनुमान है कि इसे करीब 19 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लान्च किया जा सकता है।

फ्लाइट में 60प्रतिशत सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट मे 60प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने देने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइट में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60प्रतिशत सीटें बिना चार्ज उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था। मंत्रालय के अनुसार, इस मुद्दे की समीक्षा के दौरान फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइंस की ओर से आपत्तियां भेजी गईं। इनमें आपरेशनल असर, किराए पर प्रभाव और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ व्यवस्था से तालमेल जैसे मुद्दे उठाए गए। मंत्रालय ने कहा कि व्यापक जांच पूरी होने तक 60प्रतिशत सीटें मुफ्त देने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। मौजूदा नियम 20प्रतिशत सीटों पर ही लागू होता है मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20प्रतिशत सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एयरलाइंस पंसद की सीटें चुनने पर 500 से 3000 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। प्रेफर्ड सीट के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस अक्सर देखा जाता है कि टिकट बुकिंग के बाद जब यात्री वेब चेक-इन करते हैं, तो उन्हें फ्री सीट के नाम पर केवल 20प्रतिशत आप्शन ही मिलते हैं।

आटो बाजार में एसयूवी से लेकर लग्जरी कारों तक कई नए विकल्प

नई दिल्ली

कार बाजार के लिए मार्च 2026 बेहद रोमांचक रहा, जहां काम्पैक्ट एसयूवी, सेडान और प्रीमियम सेगमेंट में कई नई गाड़ियों की एंट्री हुई। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को इस महीने लान्च किया गया, जिसकी कीमत 10.69 लाख से 18.99 लाख रुपये के बीच है। इसमें अपडेटेड डिजाइन, नए अलाय व्हील्स, 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और मसाजिंग सीट्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। इंजन आप्शन पहले जैसे ही हैं, लेकिन 1-लीटर इंजन में नया 8-स्पीड आटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल किया गया है।

हयूदै एक्टर फेसलिफ्ट को भी नए डिजाइन और फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें सनरूफ, 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और बेहतर सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 5.80 लाख से 9.57 लाख रुपये तक है और इसमें पेट्रोल के साथ सीएनजी आप्शन भी मिलता है। सेडान सेगमेंट में हयूदै वेरना फेसलिफ्ट लान्च हुआ है, जिसमें लेवल-2 अडास, 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। इसकी कीमत 10.98 लाख से 18.25 लाख रुपये है। नई रिनाल्ट डस्टर का नया जेनरेशन भी बाजार में उतारा गया है, जो रग्ड डिजाइन और माडर्न केबिन के साथ आता है। इसकी कीमत 10.49 लाख से 18.49 लाख रुपये रखी गई है। प्रीमियम सेगमेंट में लेक्सस ईएस का 8वां जेनरेशन लान्च हुआ है, जिसमें 580 किमी रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 89.99 लाख रुपये है। इसके अलावा आडी एसक्यू 8 भी लान्च हुई है, जो 1.78 करोड़ रुपये की कीमत और दमदार वी 8 इंजन के साथ 4.1 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

नया प्रीमियम टैबलेट वीवी पेड 6 प्रो चीन में लान्च

नई दिल्ली

चाइनीज कंपनी वीवो ने अपना नया प्रीमियम टैबलेट वीवी पेड 6 प्रो चीन में लान्च कर दिया है। यह डिवाइस हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भी प्रदर्शित किया गया था। इस टैबलेट की शुरुआती कीमत सीएनवाय 4,499 (करीब 61,600 रुपये) रखी गई है, जिसमें 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज मिलता है। वहीं इसका टाप वेरिएंट 16जीबी रैम और 512जीबी स्टोरेज के साथ सीएनवाय 6,699 (लगभग 91,800 रुपये) में उपलब्ध होगा। यह डिवाइस 3 अप्रैल से चीन में बिक्री के लिए आएगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 13.2 इंच का बड़ा 4के एलसीडी स्क्रीन दिया गया है, जो 144एचझेड रिफ्रेश रेट और 540 एचझेड टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है। परफार्मेंस के लिए इसमें क्वालकाम स्नेपड्रेगन 8 इलाइट जेन 5 प्रोसेसर लगाया गया है, जो 3 एनएम टेक्नोलाजी पर आधारित है और इसे हाई-एंड स्मार्टफोन जैसी ताकत देता है। बैटरी के मामले में भी यह टैबलेट काफी मजबूत है। इसमें 13,000 एमएएच की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वायफाय 7, ब्ल्यूटूथ 5.4 और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही, 8-स्पीकर आडियो सिस्टम इसे बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। यह टैबलेट स्टाइलस और कीबोर्ड सपोर्ट के साथ आता है, जिससे यह प्रोफेशनल काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए उपयोगी बन जाता है।

टेस्ला ने फ्लैगशिप माडल्स एस और एक्स का प्रोडक्शन बंद किया

वाशिंगटन। टेस्ला ने अपने फ्लैगशिप माडल्स एस और माडल एक्स का प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर बंद किया है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने पुष्टि की कि अब इन दोनों माडल्स के लिए कोई कस्टम आर्डर नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में ग्लोबल इन्वेंट्री में केवल 600 से भी कम यूनिट्स उपलब्ध हैं, और ग्राहक केवल पहले से कान्फिगर किए गए व्हीकल ही खरीद सकते है, जिसमें ज्यादातर यूनिट्स अमेरिका में हैं। माडल एस 2012 में लान्च हुई थी और यह टेस्ला की पहली मास-मार्केट कार थी। 2015 और 2016 मे यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्लग-इन ईवी बन गई थी। इसके बाद माडल एक्स 2015 मे लान्च हुई, जिसमें फैल्कन-विंग दरवाजों जैसी खास और अनोखी खूबियां थीं। दोनों माडल्स की कुल मिलाकर 610,000 से ज्यादा यूनिट्स दुनियाभर में बिकीं। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इन दोनों माडल्स की बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजार में टेस्ला इन माडल्स को उपलब्ध नही कराती, लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी यह ट्रेंड देखा गया। 2023 में कंपनी ने इनके अलग-अलग बिक्री आंकड़े जारी करना बंद कर दिए और इन्हें अन्य माडल्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया। 2025 के मध्य में दोनों माडल्स में कुछ छोटे-मोटे डिजाइन बदलाव किए गए थे और कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई थी। हालांकि, नए लग्जरी ईवी के बढ़ते काम्पिटिशन के चलते इन बदलावों से डिमांड को दोबारा बढ़ाने में खास असर नहीं पड़ा। अब जबकि बहुत ही लिमिटेड स्टाक बचे हैं और नए आर्डर नहीं लिए जा रहे हैं, उम्मीद है कि बची हुई यूनिट्स भी जल्द बिक जाएंगी। इस फैसले के साथ ही टेस्ला के दो सबसे पापुलर माडल्स का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है।

चार्ल्सटन ओपन : जेसिका पेगुला ने एलिसाबेट्टा कोच्चियारेटो से लिया बदला, क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली

अमेरिका की शीर्ष वरीय और गत चैंपियन जेसिका पेगुला ने शानदार वापसी करते हुए एलिसाबेट्टा कोच्चियारेटो को हराकर चार्ल्सटन ओपन 2026 के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। पेगुला ने यह मुकाबला 1-6, 6-1, 7-6 (7/1) से अपने नाम किया। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें उन्हें जीत के लिए अंतिम सेट के टाईब्रेक तक संघर्ष करना पड़ा।

दुनिया की नंबर 5 टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने यह जीत उस मुकाबले के एक दिन बाद हासिल की, जिसमें उन्होंने कजाकिस्तान की यूलिया पुतिन्त्सेवा को तीन घंटे से अधिक चले मुकाबले में हराया था। यह जीत उनके लिए खास रही क्योंकि पिछले साल विंबलडन में एलिसाबेट्टा कोच्चियारेटो ने उन्हें हराकर बड़ा उलटफेर किया था।

मुकाबले की शुरुआत में एलिसाबेट्टा कोच्चियारेटो ने शानदार खेल दिखाते हुए पहला सेट आसानी से जीत लिया। इस दौरान जेसिका पेगुला की सर्विस काफी कमजोर रही और वह पहले सेट में केवल 25 प्रतिशत फर्स्ट सर्व पाइंट ही जीत सकीं। मैच के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन को लेकर निराशा भी जताई।

हालांकि दूसरे सेट में जेसिका पेगुला ने जोरदार वापसी की और मैच को बराबरी पर ला दिया। तीसरे सेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां वह एक समय 1-4 से पीछे चल रही थीं, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 4-4 कर दिया और मुकाबले को टाईब्रेक तक पहुंचाया।

निर्णायक टाईब्रेक में जेसिका पेगुला ने बेहतरीन खेल दिखाया और एलिसाबेट्टा कोच्चियारेटो की गलती का फायदा उठाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ उन्होंने पिछले साल की हार का बदला भी पूरा कर लिया।

अब क्वार्टरफाइनल में जेसिका पेगुला का सामना रूस की डायना श्नाइडर से होगा, जिन्होंने कनाडा की लेयला फर्नांडीज को 6-3, 6-0 से हराया।

स्विट्जरलैंड की तीसरी वरीय बेलिंडा बेनसिच ने भी अगले दौर में जगह बनाई। उन्होंने चेक गणराज्य की सारा बेजलेक को 7-6 (7/4), 6-2 से हराया। अब उनका मुकाबला अमेरिका की मैडिसन कीज से होगा, जिन्होंने हंगरी की अन्ना बोंडार को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी।

न्यूज ब्रीफ

अलाना किंग के पांच विकेट से आस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया, सीरीज में किया क्लीन स्वीप

नई दिल्ली। आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराकर सीरीज पर क्लीन स्वीप कर लिया। यह मुकाबला बासेटेरे में गुरुवार (2 अप्रैल) को खेला गया, जहां लेग स्पिनर अलाना किंग के पांच विकेट ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वेस्टइंडीज की अच्छी शुरुआत, फिर पारी बिखरी पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में 49/1 का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन इसके बाद टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। 19वें ओवर तक स्कोर 78/5 हो गया। ओपनिंग में 38 रन की साझेदारी के अलावा रीएलियाना ग्रिमोंड और चिनेल हेनरी के बीच 37 रन की साझेदारी ही कुछ हद तक टीम को संभाल सकी। ग्रिमोंड 27वें ओवर में किंग का शिकार बनीं, जिसके बाद पूरी टीम तेजी से सिमट गई। हेनरी ने 42 रन बनाकर नाबाद पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास समर्थन नहीं मिला और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 35.4 ओवर में 136 रन पर आलआउट हो गई। अलाना किंग की घातक गेंदबाजी अलाना किंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 5 विकेट झटके और मैच की सबसे बड़ी नायिका रहीं। उनके अलावा एशले गार्डनर ने भी 2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया।

मैं आईपीएल चेयरमैन होता तो संजीव गोयनका पर प्रतिबंध लगा देता : ललित मोदी

लंदन। आईपीएल के संस्थापक रहे ललित मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार लखनऊ सुपर जाएंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने टीम के कप्तान ऋषभ पंत से व्यवहार किया है। ऐसे में अगर वह आईपीएल चेयरमैन होते तो गोयनका पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनसे टीम का मालिकाना अधिकार भी वापस ले लेते। ललित मोदी ने ये बात दिल्ली कैपिटल्स से पहला ही मैच हारने के बाद गोयनका के कप्तान ऋषभ पंत और सहयोगी स्टाफ से मैदान में ही हो रही बातों को देखकर कही है। प्रशंसकों को इसी के साथ ही आईपीएल 2024 याद आ गया जब गोयना इसी प्रकार से केएल राहुल पर भड़क गये थे। इसके बाद राहुल ने सुपर जाएंट्स टीम छोड़ दी थी। अब ऋषभ के साथ वही व्यहार हुआ है। जिससे प्रशंसक नाराज हैं। ऐसे में मोदी ने गोयनका को आईपीएल से प्रतिबंधित करने के साथ ही मालिकाना अधिकार वापस लेने की मांग की है। वहीं इस मामले में आलोचना इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान ने इस भी की है। उन्होंने कहा , टूर्नामेंट में इस प्रकार की बातों के लिए जगह नहीं है। वान के इस पोस्ट पर मोदी ने लिखा कि अगर वह अभी भी आईपीएल कमिश्नर होते तो वह संजीव गोयनका को प्रतिबंधित करने के साथ ही टीम का मालिकाना अधिकार भी वापस ले लेते।

पीटरसन ने की दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी की तारीफ

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान क्रिकेटर केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे बल्लेबाज समीर

रिजवी की जमकर प्रशंसा की है। रिजवी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलायी है। पीटरसने पिछले साल कैपिटल्स के मेंटर रहे थे। उनका कहना है कि पिछले सीजन में ही उन्होंने समीर की प्रतिभा देख ली थी। तभी से वह इस युवा बल्लेबाज के खेल से प्रभावित हैं। उन्होंने टीम प्रबंधन से अपील की है कि वह इस युवा का साथ देते रहे। जिससे उसका आगे भी इसी प्रकार खेलने के लिए मनोबल बढ़ता रहे। पीटरसन ने कहा, उन्होंने हालात के हिसाब से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और इसमें मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने पिछले सीजन में समीर के साथ काफी समय बिताया था और उन्हें बहुत करीब से देखा था। उन्होंने एक अभ्यास मैच में भी शतक बनाया था पर टूर्नामेंट के पहले चरण में उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। हालांकि जब सत्र के बाद के हिस्से में उन्हें अवसर मिला, तो उनकी क्षमताएं सभी ने देखीं। तब हर किसी ने उनकी तरफ देखा और कहा इसमें काफी संभावनाएं नजर आती है।

जेम्स रोड्रिगेज अस्पताल में भर्ती, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले कोलंबिया को बड़ा झटका

नई दिल्ली

कोलंबिया के कप्तान जेम्स रोड्रिगेज को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से कुछ महीने पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे उनके खेलने को लेकर उनके प्रसंशको के बीच चिंता बढ़ गई है।

रोड्रिगेज ने हाल ही में कोलंबिया राष्ट्रीय फुटबाल टीम के लिए फ्रांस राष्ट्रीय फुटबाल टीम के खिलाफ खेले गए एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा लिया था। इस मुकाबले में कोलंबिया को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा और रोड्रिगेज ने करीब एक घंटे तक मैदान पर समय बिताया। मैच के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कोलंबिया फुटबाल संघ ने बयान जारी कर बताया, फ्रांस के खिलाफ मैच के अगले दिन खिलाड़ी को गंभीर डिहाइड्रेशन की समस्या हुई, जिसके कारण पिछले 72 घंटों से उन्हें अस्पताल में रखकर निगरानी और रिकवरी कराई जा रही है।

क्या वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकते हैं रोड्रिगेज

फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भागीदारी पर खतरा है। संघ ने साफ किया है कि यह समस्या खेल से जुड़ी नहीं है।

संघ के अनुसार, मिनेसोटा के एक मेडिकल सेंटर से मिली जानकारी के अनुसार मिडफील्डर एक गैर-खेल संबंधी मेडिकल स्थिति के चलते डाक्टरों की निगरानी में हैं। यह स्थिति न तो मांसपेशियों से जुड़ी है और न ही उनके फुटबाल करियर से।

टीम के लिए कितने अहम हैं जेम्स रोड्रिगेज

जेम्स रोड्रिगेज कोलंबिया के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2014 में गोल्डन बूट जीतकर दुनियाभर में पहचान बनाई थी। अब तक वह कोलंबिया के लिए 31 गोल और 41 असिस्ट कर चुके हैं और 2024 में टीम को कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उम्मीद है कि वह जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे।

एक दशक बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी आस्ट्रेलियाई टीम

सिडनी। आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इसी साल सितंबर में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। इस दौरे में आस्ट्रेलिया तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलेगी। आस्ट्रेलियाई टीम एक दशक के बाद जिम्बाब्वे जा रही है। इससे पहले वह साल 2014 में जिम्बाब्वे गयी थी। सीरीज 15 सितंबर को शुरू होगी, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 18 और 20 सितंबर को खेला जाएगा। ये सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। वहीं इस दौरे को लेकर जिम्बाब्वे बोर्ड उत्साहित हैं। उसका मानना है कि इससे टीम को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की तैयारी का अवसर मिलेगा। टी20 विश्कप के मेजबानों में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ जिम्बाब्वे, भी शामिल है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने कहा कि यह दौरा टीम के लिए एक अहम मोड़ पर आया है। उन्होंने कहा, हमें आस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे में फिर से स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह एक बेहद रोमांचक एकदिवसीय सीरीज होने की उम्मीद है। शीर्ष स्तर की टीम के खिलाफ मैच से ही हमारी टीम आगे बढ़ेगी। ये टीम के विकास के लिए भी बहुत जरूरी हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 नजदीक आ रहा है, ऐसे में यह दौरा हमें अपनी तैयारियों को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर देता है। हम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यह हमारे प्रशंसकों के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि वे अपने घर पर ही विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का आनंद उठा सकें। हमें उम्मीद है कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हमें अपने प्रशंसकों का जोरदार समर्थन मिलेगा। हाल के दिनों में जिम्बाब्वे ने आस्ट्रेलिया को कई बार टक्कर दी है। इसी साल फरवरी में हुए टी20 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने आस्ट्रेलिया की टी20 टीम को 23 रनों से हराया था। इसके अलावा आस्ट्रेलिया की 50 ओवरों की टीम को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2022 में टाउन्सविले में खेले गए इस मैच में आस्ट्रेलिया तीन विकेट से हार गयी थी। आस्ट्रेलिया के जिम्बाब्वे दौरे पर सभी मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे। पहला एकदिवसीय 15 सितंबर, दूसरा 18 सितंबर और तीसरा 20 सितंबर को खेला जाएगा।

अभिषेक शर्मा पर लगा जुर्माना, आन-फील्ड रिएक्शन पड़ा भारी

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के उपकप्तान अभिषेक शर्मा को उनके आन-फील्ड व्यवहार के लिए जुर्माना झेलना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताना उन्हें भारी पड़ गया।

अंपायर के फैसले पर जताई नाराजगी

मैच के दौरान अभिषेक शर्मा को एक कैच आउट दिया गया, जिसे वरुण चक्रवर्ती ने लपका था। हालांकि इस फैसले की जांच भी की गई, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसे सही करार दिया। इसके बावजूद अभिषेक शर्मा कुछ देर तक क्रीज पर खड़े रहे और निराशा जताते हुए इशारे करते नजर आए। उनके इस व्यवहार को आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभिषेक शर्मा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया। यह कार्रवाई आईपीएल की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के तहत की गई, जिसमें मैच रेफरी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है।

शानदार पारी के बावजूद विवाद

हालांकि इस विवाद के बीच अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 48 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 34 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक साझेदारी भी की।

एसआरएच ने दर्ज की बड़ी जीत

मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 226/8 का विशाल स्कोर बनाया। हेनरिक क्लासेन (52) और नितीश कुमार रेड्डी (39) ने अहम योगदान दिया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 16 ओवर में 161 रन पर सिमट गई। अंगकृष रघुवंशी ने 52 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स : फुटबॉल में छत्तीसगढ़ को रजत पदक

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम, कोटा में खेले गए पुरुष फुटबाल के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में छत्तीसगढ़ को पराजय का सामना कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित किया। छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार तालमेल, तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा का परिचय दिया। फाइनल में कड़े मुकाबले में पश्चिम बंगाल से 0-1 से मिली हार खिलाड़ियों ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए हर पल मुकाबले को संतुलित बनाए रखा। हाफ टाइम तक पश्चिम बंगाल की टीम 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। छत्तीसगढ़ की टीम ने लगातार आक्रमण कर गोल उतारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, विभिन्न विभागों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी और खेलप्रेमी बड़ी संख्या में फाइनल मैच देखने के लिए मैदान में पहुंचे थे।

आईपीएल में टीमों को बढ़ाने पर विचार कर रहा बीसीसीआई : अरुण धूमल

टूर्नामेंट की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे

मुम्बई

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) साल 2008 में शुरु होने के बाद से ही लगातार छाया हुआ है। यहां तक कि आज आईपीएल दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इसके मैचों का प्रसारण दूनिया भर में होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की सबसे अधिक कमाई आईपीएल से ही होती है। ऐसे में बोर्ड अब इसमें टीमें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के अनुसार बोर्ड टीमों की संख्या बढ़ाने का कोई भी फैसला, टूर्नामेंट की गुणवत्ता से समझौता करते हुए नहीं लेगा।

धूमल ने कहा, टीम बढ़ाने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके लिए कितना समय मिलता है। निवेशकों की इसमें कितनी रुचि है क्योंकि आईपीएल में निवेश पर असाधारण रिटर्न मिल रहा है। मैचों की संख्या बढ़ाने के पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही कहा कि अगर इस लीग को नियमित रूप से आयोजित किया जाना है, तो नई व्यवस्था होगी। आईसीसी कार्यक्रम में कम द्विपक्षीय मैच रखने होंगे। तभी लीग क्रिकेट बढ़ सकता है।

साथ ही कहा कि जब बोर्ड ने प्रसारण अधिककार 48,390 करोड़ रुपए में बेचे थे, तो योजना यह थी कि धीरे-धीरे मैचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अनुसार साल 2023 और 2024 में 74 मैच, 2025 और 2026 में 84 मैच, और अंत में साल 2027 तक 94 मैच खेले जाने थे पर ये योजना अभी रुकी हुई है। साल 2026 में भी 74 मैच ही खेले जाएंगे। इसके पीछे को कारण आईसीसी का मौजूदा भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) है, जो अप्रैल 2027 तक चलेगा, इससे मैचों के बीच बहुत कम खाली समय मिलता है। धूमल ने आईपीएल के विस्तार को लेकर कहा, लीग को 74 से 94 मैचों तक ले जाने के लिए हमें एक बड़ी विंडो की जरूरत है। ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पहले से ही बुक है। मार्च के बीच से मई के आखिर तक का समय ही हमारे पास सीमित उपलब्ध है। वहीं जून में बारिश शुरु हो जाती है। तब र्नामेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर हम मौजूदा विंडो में ही 74 से 94 मैच करवाने की कोशिश करेंगे तो हमें अधिक डबल-हेडर करवाने पड़ेंगे। जो कि प्रसारण कर्ता के लिए फायदे का सौदा नहीं होते। हमें सभी के हितों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए हमने अब तक 74 मैच ही रखे हैं।

आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कहा, हम यहां दबदबा बनाने आए हैं

बेंगलुरु

रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने साफ कर दिया है कि टीम का लक्ष्य सिर्फ एक खिताब जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक दबदबा कायम करना है। आरसीबी पाडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सीजन की सफलता टीम के लिए नई शुरुआत है।

जितेश ने कहा, यह एक साल की बात नहीं है। हम यहां दबदबा बनाने आए हैं। मैं यह साबित करना चाहता हूं कि पिछले सीजन में जो हुआ वह कोई एक बार की बात नहीं थी।

पिछले सीजन में आरसीबी की ऐतिहासिक खिताबी जीत को याद करते हुए जितेश ने इसे अपने करियर का सबसे खास पल बताया।

उन्होंने कहा, आरसीबी के लिए पहला खिताब जीतना एक जादुई एहसास था। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि मैं उसमें योगदान दे सका। यह पल हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा।

जितेश शर्मा ने अपने निजी जीवन के मुश्किल दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिता के निधन का दर्द आज भी उनके साथ है।

उन्होंने कहा, जब आप अपने पिता को खोते हैं, तो वह खालीपन कभी नहीं भरता। मैं इसे भूलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस भावना को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा हूं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके पिता ने उन्हें भारत के लिए खेलते और आरसीबी के लिए ट्राफी जीतते देखा।

जितेश ने अपने खेल और मानसिक मजबूती का श्रेय दिनेश कार्तिक को दिया। उन्होंने कहा कि कार्तिक ने उन्हें न सिर्फ तकनीकी रूप से बेहतर बनाया, बल्कि मुश्किल समय में सही सलाह भी दी।

उन्होंने कहा, डीके अन्ना ने मुझे अपने खेल को समझने और मानसिक रूप से मजबूत बनने में काफी मदद की। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी, जिससे मैं खुद को फिर से संभाल पाया।

जितेश ने कहा कि अब वह खुद को सिर्फ विकेटकीपर के रूप में नहीं देखते, बल्कि टीम के लिए एक फिनिशर और फील्डर की भूमिका भी निभाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, मेरा काम है टीम में जगह बनाना, चाहे जो भी भूमिका मिले। अब मैं खुद को एक आलराउंड योगदान देने वाले खिलाड़ी के रूप में देखता हूं।

भारतीय टीम में वापसी को लेकर जितेश ने कहा कि यह उनका सबसे बड़ा सपना है। उन्होंने कहा, भारत के लिए खेलना मेरा अंतिम लक्ष्य है। मुझे लगता है कि मैंने अपना काम किया है और अब मुझे अगले मौके के लिए तैयार रहना है। पिछले सीजन के फाइनल में 10 गेंदों पर 24 रन की अहम पारी खेलने वाले जितेश ने उस मैच के आखिरी ओवर को याद करते हुए कहा, वह छह गेंदें मेरी जिंदगी की सबसे लंबी गेंदें थीं। हम उस जीत को बहुत ज्यादा चाहते थे। डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में नए सीजन में उतर रही आरसीबी को लेकर जितेश ने कहा कि टीम हर चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इस सीजन में टीमें हमारे खिलाफ और ज्यादा आक्रामक होंगी, और मुझे यह पसंद है। मैं चाहता हूं कि लोग हम पर दबाव डालें, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से जवाब देंगे।

डिब्बाबंद खानों पर आंख मूंदकर न करें विश्वास

इस भागदौर भरी जिंदगी में लोगों को हर काम में जल्दी रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो पैकेट में पीछे की ओर दी जाने वाली फाइन लाइन को नहीं पढ़ते, जहां चीज में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में लिखा होता है। पैकेट में सामने की और लिखे फैट फ्री, जीरो कोलेस्ट्रॉल जैसे शब्द पढ़ते ही वस्तु की खरीदारी कर लेते हैं। परिणामस्वरूप लंबे समय तक लो फैट बिस्कुट और जीरो कोलेस्ट्रॉल वाली ब्राउन बैड खाकर भी उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्रिग्लीसिराड लेवल में बदलाव नहीं होता। लो फैट और एनर्जी फूड का सेवन करके भी पूरे दिन थकावट महसूस होती रहती है।

जीरो कोलेस्ट्रॉल/कोलेस्ट्रॉल फ्री

हालांकि वनस्पति तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, पर यह वसा ही है। आमतौर पर हम मक्खन का चुनाव करते हैं, क्योंकि इसमें सेचुरेटेड फैट कम होता है। वनस्पति तेल की एक चम्मच में 14 ग्राम वसा और सौ कैलोरी होती है, इतनी ही मात्र एक चम्मच मक्खन क्रीम से मिलती है। ऐसे में खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका बनी ही रहती है। यही कारण है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और वजन में अंतर देखने को नहीं मिलता। बेहतर होगा कि हम वनस्पति तेल के उपभोग की मात्र को सीमित करें। कोलेस्ट्रॉल फ्री खाद्य वस्तुओं में सैचुरेटेड वसा प्रतिशत जानें।

फैट फ्री/लो फैट

यदि किसी खाने के पैकेट पर लो फैट या फैट फ्री लिखा है तो वह खाना सेहत के लिए कितना अच्छा है, इससे जानने के लिए उसके न्यूट्रीशनल फैक्ट्स अवश्य पढ़ें। आमतौर पर इन खानों में प्राकृतिक वसा तो कम होती है, पर कम वसा के कारण स्वाद में आई कमी की क्षतिपूर्ति सोडियम, अधिक शुगर और थिकनर जैसे इमल्सीफायर मिलाने से कर दी जाती है, जिससे नुकसान की आशंका भी बनी रहती है। उदाहरण के लिए प्रोपीलीन ग्लाइकोल, एक कृत्रिम घोल है, जो खाद्य पदार्थो में इमल्सीफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसकी पहचान त्वचा और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिक के रूप में भी होती है। इसके अलावा, इस तरह के खानों से संतुष्टि नहीं मिलती, तो इन्हें खाने के बाद आपकी इच्छा और खाने की बढ़ जाती है। सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, डी, ई आदि वसा में घुलनशील होते हैं यानी उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए शरीर को कुछ वसा की जरूरत होती है, पर वसा से दूर रहने के कारण है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हर समय थकावट महसूस करते हैं और भूख लगती रहती है।

नो एडीटिव

यह लाइन कुछ खास जूस, ब्रेड और अनाजों पर देखने को मिलती है, पर किसी चीज में शुगर कई तरह से हो सकती है जैसे हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप, शहद और लेक्टोस आदि। नो एडिटिव व नेचुरल आदि शब्द उलझन को बढ़ा देते हैं, इनके संबंध में नियम भी नहीं है। बेहतर होगा कि शुगर फ्री या नो शुगर आदि शब्दों पर गौर करें। यदि किसी चीज में एक समय के भोजन में 400 से अधिक कैलोरी मिल रही है तो चुनाव समझकर ही करें।

कब्र के नीचे परिवार सहित रहते हैं लोग

अमूमन आपने सुना व देखा हो कि इंसान के मरने के बाद उसे जला दिया जाता है या उसे दफना दिया जाता है। यह सब करने के बाद सब उसे भूल जाते हैं। अगर इंसान को दफनाया जाता है तो हम कभी कभार उसकी कब्र की देखभाल कर आते हैं। हर कोई यह समझता है है कि श्मशान घाट हो या कब्र। इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा भूत बनकर वहां पर उपस्थित रहती है और हर कोई वहां पर जाने से डरता है। लेकिन आपको बता दें कि मिस्त्र देश का एक शहर ऐसा है जहां पर लोग मरे हुए इंसान की इस तरह से कब्र बनवाते हैं कि कब्र की देखभाल करने के लिए वहां पर देखभाल करने वाला अपने परिवार के साथ रह सकें।

नींद की गोली खाते हैं तो हो जाएं सावधान

टैंशन और मानसिक तनाव को अपने से दूर रखने बहुत सारे लोग नींद की गोलियों का सेवन करते हैं। वहीं कुछ लोग सर्दी, फ्लू, बुखार एलर्जी और बढ़िया नींद लेने के लिए भी एंटी-कोलीनर्जिक युक्त गोलियों लेते हैं, शायद वह यह नहीं जानते कि इस तरह की दवाओं का सेवन करने से वह अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। नींद की गोली हमारे दिमाग पर बुरा असर डालती है। यह बात हम नहीं बल्कि बहुत सारे शोधों में कही गई है।

बच्चों को हाथ धोना जरूर सिखाएं

आमतौर पर बच्चे हाथ धोने को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं होते। न तो वे खाने से पहले हाथ धोना पसंद करते हैं और न ही बाथरूम के बाद ही उन्हें अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करना पसंद होता है। खेलने के बाद सीधा खाने की मेज पर बैठ जाना तो बच्चों के मामले में आम बात है। लेकिन, ऐसा नहीं है कि बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, तो आप उन्हें कहना बंद कर दें। हाथ धोना कीटाणुओं से बचने का सबसे कारगर तरीका है। इससे आप रोगाणुओं को फैलने से रोक सकते हैं और साथ ही अपने बच्चों को कई संक्रमणों से बचा सकते हैं।

कीटाणुओं से बचने का पहला उपाय

बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यस्कों के मुकाबले कमजोर होती है, इसलिए आपको चाहिए कि उनकी खास देखभाल करें। कीटाणु भी इस प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं-

- गंदे हाथों से छूने।
- गंदे डायपर बदलते समय।
- दूषित पानी और भोजन के जरिए।
- छींक अथवा खांसी के समय आने वाली बूंदों से।
- दूषित सतहों से।
- बीमार व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ के साथ संपर्क के माध्यम से।

जब बच्चे कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, तो वे जाने-अनजाने ही उससे संक्रमित हो जाते हैं। वे उन हाथों से कभी आंखों, कभी नाक और मुंह को छूते हैं। इससे कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वे बीमार पड़ जाते हैं। एक बार अगर बच्चा किसी संक्रमित रोग से ग्रस्त हो जाए, तो पूरे परिवार के रोग ग्रस्त होने की आशंका रहती है।

कीटाणुओं से बचने के लिए क्या करें

- भोजन से पहले हाथ जरूर धोएं।
- शौच के बाद भी हाथ धोना बहुत जरूरी है।
- घर की साफ सफाई के बाद हाथ अवश्य साफ करें।
- पालतू जानवरों से खेलने के बाद।
- किसी बीमार व्यक्ति से मिलकर आने के बाद।
- छींक या खांसी के बाद।
- खेलने या बागवानी के बाद।

हाथ धोना सुरक्षा की दीवार

अच्छी तरह से हाथ धोना कई बीमारियों से बचने की पहली रक्षा पंक्ति होती है। सिर्फ अच्छी तरह से हाथ धोने से ही आप सामान्य ठंड से लेकर, दिमागी बुखार, श्वासनलिकाशोथ, इन्फ्लूएंजा, हेपेटाइटिस ए, और संक्रामक दस्त तक से बच सकते हैं।

ऐसे धोएं अपने हाथ

बच्चों को अच्छी तरह हाथ धोने की आदत डालें। उन्हें अपने साथ खड़ा कर हाथ धोएं। हो सके तो दोनों साथ ही हाथ धोएं। इससे उन्हें हाथ धोने का सलीका तो मालूम चलेगा ही साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी अंदाजा होगा कि आखिर हाथ धोना कितनी अच्छी आदत है।

गुनगुने पानी से धोएं हाथ

हाथ अगर गुनगुने पानी से धोए जाएं तो बेहतर। इससे अधिक संख्या में कीटाणु मरते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी अधिक गर्म न हो। अधिक गर्म पानी से बच्चों की त्वचा को नुकसान हो सकता है।

कितनी देर धोएं हाथ

साबुन से अच्छी तरह झाग बनाकर करीब 20 सेकेंड तक हाथ धोना सही रहता है। जरूरी नही कि आप एंटी बैक्टीरियल साबुन का ही इस्तेमाल करें। कोई भी साबुन कीटाणुओं को मारने में कारगर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे उंगलियों के बीच में और नाखूनों के आसपास भी अच्छी तरह से हाथ धोएं। और हां कलाई साफ करना न भूलें।

सुखाने के लिए तौलिया हो सही

हाथ धोने के बाद उसे तौलिये से पोंछ लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा जिस तौलिये से हाथ साफ कर रहा है वह साफ और सूखा हो। गंदे तौलिये से हाथ साफ करने से बच्चे के हाथ पर दोबारा कीटाणु जमा हो सकते हैं। और ऐसे में उसका हाथ धोना बेकार जाएगा।

हाथ धोने की महत्ता को नजरअंदाज न करें। हाथों की सफाई पर लगाए गए चंद सेकेंड आपके और आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लगने वाले कई चक्करों से बचा सकते हैं।

आंखों के काले घेरे हटाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं क्रीम

आखों के नीचे पड़ने वाले काले घेरे ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को कम कर देते हैं बल्कि इसके अलावा वो आपको आपकी उम्र से ज्यादा दिखाने लगते हैं। आंखों के आसपास की त्वचा कहीं ज्यादा नाजुक होती है और चेहरे के अन्य भागों की अपेक्षा पतली भी, इसलिए इसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आंख के पास काले घेरों के कई कारण हैं। यह अनुवांशिक भी हो सकता है या फिर थकावट आदि के कारण भी। इस लेख में हम आपको आंखों के काले घेरे से निपटने के लिए घर में बनने वाली अंडर आई क्रीम के बारे में बता रहे हैं।

अडंर आई क्रीम बनाने की विधि

दो सॉस पैन, दो ग्लास, चम्मच, थर्मोमीटर, हैंडहेल्ड मिक्सर, कोकोनट तेल, प्रिमरोज, विटामिन ई, लैवेंडर ऑयल आदि लें। घर में आखों के नीचे के काले घेरे मिटाने के लिए एक मध्यम आकार के सॉसपैन को लें और उसमें कोकोनट तेल, प्रिमरोड, विटामिन ई को थोड़ें से पानी के साथ गर्म करें। सारे तेल के आपस में अच्छी तरह मिल जाने के बाद आप उसमें लैवेंडर ऑयल को मिलाएं। ये मिक्सर ठंडा होने तक तरल ही रहेगा। अगर आपको इसे ज्यादा जल्दी चाहिए तो आप इसे फ्रिज में रख लों। जब ये मिक्सर गाढ़ा हो जाए को एक जार में भर कर रख लें। आप रात में इसका प्रयोग कर ना शुरू पर भी कर सकती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इन तेलों का आपकी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है।

काले घेरे दूर करने के उपाय

चाय की पत्ती को रातभर दूध में भिगोकर रखें। अब चाय की पत्ती को दूध में अच्छे से मिक्स करके डार्क सर्कल्स पर लगाएं। कुछ ही दिन में आपको फर्क महसूस होगा। आंखों के काले घेरों को हमेशा के लिए हटाने के लिए खीरे के पतले पतले स्लाइस काटकर आंखों पर लगभग 10 तक मिनट रखें। ऐसा करने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है और कुछ ही दिन में डार्क सर्कल्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगें। बादाम का तेल कई प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है जो आंखों के आसपास की त्वचा को फायदा पहुंचाता है। बादाम के तेल के नियमित उपयोग से त्वचा का रंग हल्का पड़ जाता है, इसीलिए इसे आंखों के आसपास लगाने से डार्क सर्कल दूर हो जाते है। रात में इसे आंखों के नीचे थोड़ा सा लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने के बाद ऐसा ही छोड़ दें। सुबह उठने के बाद मुंह धो लें। यह ध्यान रखें कि आपके आंखों के नीचे की त्वचा से कोई भी सीधा संपर्क कोमल होना अत्यावश्यक है, क्योंकि यह आपके शरीर की सबसे नाजुक त्वचा में से एक है।

अनेक स्किल्स में माहिर होने की जरूरत

वॉटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बनाएं कॅरियर

जल इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है,लेकिन इतने विकास के बावजूद विश्व की एक बड़ी जनसंख्या आज भी स्वच्छ पेयजल से वंचित है। कृषि, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता में पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदलाव आए हैं और खेद की बात है कि स्थिति में कोई सुखद सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में काफी काम किया जाने लगा है जिसके चलते वॉटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कॅरियर बनाने के अनेक अवसर सामने आ रहे हैं।

योग्यता...

चूंकि वॉटर मैनेजमेंट एक जटिल विषय है इसलिए इससे संबंधित कार्य करने के लिए अनेक स्किल्स में माहिर व्यक्ति की जरूरत होती है। फील्ड को-ऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य पाने के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री काफी पसंद की जाती है। भू-जल और कृषि के क्षेत्र में शोध करने वाली कंपनियां जियोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी में मास्टर्स एवं पीएचडी डिग्री धारकों को काम पर रखती हैं। आजकल इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पब्लिक पॉलिसी डिग्रियों का भी प्रचलन देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि अक्सर अनेक सीमाओं से गुजरने वाले जल यानि नदियों आदि को लेकर अनेक विवाद भी जन्म ले सकते हैं। ऐसे में पानी से संबंधित पब्लिक पॉलिसी पर भी जोर दिया जाने लगा है।

इंस्टीट्यूट वॉच...

- आईआरएमए आनंद इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद
- टीआईएसएस इंस्टीट्यूट, मुंबई
- क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया
- उपसला यूनिवर्सिटी, स्वीडन

पारिश्रमिक...

जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले फील्ड वर्कर या को-ऑर्डिनेटर प्रतिमाह 10 हजार रुपए या अधिक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर 25 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। किसी कंपनी में बतौर कंसल्टेंट कार्य करने वाले 35 हजार से 1 लाख रुपए प्रतिमाह तनख्वाह पाते हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से कंसल्टेंसी चलाने वाले इससे कहीं अधिक आय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले प्रोफेशनल भी पद और अनुभव के अनुसार काफी अच्छी आय हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वॉटर मैनेजमेंट में आप एक बेहतर भविष्य देख सकते हैं।

रेसिपी

पालक ढोकला

सामग्री

1 कप बेसन, 2 गुच्छा पालक, 1/4 कप दही (फेंटी हुई), 1 इंच पीस अदरक, 2-3 हरी मिर्च, 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शक्कर, नमक (स्वादअनुसार), 1 चम्मच ईनो, छौंकने की सामग्री, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, 2 चम्मच तिल, 4-5 कड़ी पत्ती, 1/4 हींग

विधि

ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले आप पालक को अच्छे से धो कर काट लें। अब इसे भाप में पका कर ठंडा कर लें और इसमें अदरक और हरी मिर्च पीस कर मिला दें। ध्यान में रखें कि यह प्यूरी लगभग 1 कप हो। इसके बाद एक बड़ा कटोरा लेकर उसमें बेसन, पालक की प्यूरी, दही और तेल मिलाएं। घोल को पतला करने के लिए इसमें पानी मिला दें। घोल ज्यादा पतला और गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें नमक, शक्कर और नींबू मिला कर 5-10 मिनट के लिए रख दें। बाद में इस घोल में ईनो मिला लें। उसके तुरंत बाद ही तेल लगे सांचे में घोल भरें। ढोकलों को स्टीमर में डाल कर 15-20 मिनट तक गैस की तेज आंच पर पकाएं। बाद मे गैस को बंद कर दें। स्टीमर से ढोकलों को निकाल कर 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखें।

छौंक लगाने की विधि: एक पैन में हींग, राई, तिल और कड़ी पत्ती डालें और गैस पर रख कर तड़का तैयार कर लें। बाद में गैस को बंद कर दें। अब इसे ढोकलों के चारों ओर से ऊपर डालें और हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।

क्रिस्पी सोया चिली रेसिपी

सामग्री

100 ग्राम सोया चंक्स, 1 बड़ी शिमला मिर्च, 3 बड़े प्याज (मोटे कटे हुए), छोटी कटोरी हरे प्याज, 1 कटोरी ब्रोकली, 1 चम्मच अदरक-लहुसन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून मक्की का आटा, 1 चम्मच सोया सॉस,1 विनेगर, 1 चम्मच टमैटो केचप, तेल आवश्यकतानुसार, नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च स्वादानुसार

विधि

सोया चंक्स को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोएं रखें फिर निचोड़ कर निकालें। अब उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहुसन की पेस्ट, मक्की का आटा अच्छी तरह मिक्स करें और बाद में इन्हें डिप फ्राई कर लें। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, उसमें लहसुन और प्याज मिलाकर ब्राउन होने तक भूनें। बाद में उसमें शिमला मिर्च, ब्रोकली और हरे प्याज डालें। 2 मिनट के बाद फ्राई सोया उसमें डालें। सारे मिश्रण को अच्छे से उल्टे-पल्टे। अब उसमें सोया सॉस, विनेगर, टैमटो केचप, नमक और हरी मिर्च डालें और अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिनट तेज आंच पर पकाएं। फिर हरे धनिएं से रैसिपी को सजाकर सर्व करें।

प्रोस्टेट कैंसर को जानने की दिशा में नई पहल

वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए यह पता लगाया है कि कुत्ते मूत्र के नमूनों को सूंघकर 90 प्रतिशत स्टीकता के साथ प्रोस्टेट कैंसर का पता लगा सकते हैं। इस शोध से यह उम्मीद जगी है कि इंसानों में कैंसर और संक्रामक बीमारियों की पहचान करने में कुत्तों की सूंघने की क्षमता काफी मददगार साबित हो सकती है।

रक्त परीक्षण के जरिए की जाती है बीमारी की पहचान

शोध के दौरान 2 जर्मन शैफर्ड कुत्तों को 900 पुरुषों का मूत्र सुंघाया गया, जिनमें से 360 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर था, जबकि 540 लोगों को यह बीमारी नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 प्रतिशत मामलों में दोनों कुत्तों ने बीमारी की पहचान कर ली। हालांकि मिलान के रिसर्च सेंटर और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि प्रोस्टेट कैंसर की पहचान के लिए कुत्तों की सूंघने की क्षमता कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, इस बारे में और रिसर्च किए जाने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में इस बीमारी की पहचान रक्त परीक्षण के जरिए की जाती है जिसे पीएसए टेस्ट के तौर पर जाना जाता है। हालांकि यह प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जाता। इससे पहले किए गए शोधों में भी यह पाया गया था कि कुत्ते 93 प्रतिशत की स्टीकता के साथ प्रोस्टेट कैंसर का पता लगा सकते हैं।

मधुमेह से लड़ने में मदद करेगा मोबाइल एप

शोधकर्ताओं ने ऐसी मोबाइल एप तैयार की है जोकि मधुमेह से लड़ने में मदद करेगी। इस एप के जरिए लोग अपो खाने-पीने की आंदतों और कसरत आदि पर नजर रख पाएंगे। इस एप में मधुमेह से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली के कारण मौजूदा समय में मधुमेह का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह एप इस बीमारी से बचाव में काफी मददगार साबित हो सकता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**